मासिक पत्रिका RAJHIN/2007/21229 वर्ष-01, अंक नं. 05

जयपुर टाइम्स

राजस्थान की रग-रग से निकली बात
जयपुर टाइम्स मैग्जीन के साथ

बाढ़ में बहे खेत,
पर उम्मीद अभी जिंदा है
चलो साथ मिलकर उसे थामें।

विकसित राजस्थान फिल्म की पटकथा.... 04

भजनलाल सरकार ने लिखी विकसित राजस्थान फिल्म की पटकथा, निर्माण शुरू

मोदी के पसंदीदा ऑफिसर है पंत..... 10

पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे पसंद के ऑफिसर हैं सुधांशु पंत

अशोक गहलोत की प्रदेश राजनीति में..... 17

फिर से प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत जोरों से सक्रिय

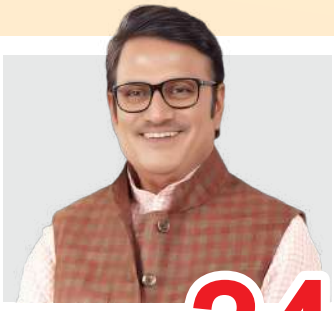

राठौड़ भाजपा के दबंग कार्यकर्ता.... 24

संघर्ष का दूसरा नाम 'राजेंद्र राठौड़', बन गए राजस्थान भाजपा के दबंग योद्धा

हिंदुत्ववादी नेता के रूप में साबित..... 30

प्रखर राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी नेता के रूप में खुद को साबित किया है जवाहरसिंह बेडम ने

भजनलाल के सपने साकार कर रहे गौतम..... 37

अमित शाह और भजनलाल के सपने को साकार कर रहे गौतम कुमार

गहलोत, शाह की पहली पसंद..... 44

चुनाव के दौरान ही अमित शाह ने कर ली थी 'हीरे' की परख

प्रकाशक, मुद्रक
रामेश्वर लाल जाट

संपादक
नीतू चौधरी

उप संपादक
कुमकुम रंगा, रूपचंद गुर्जर, रोहित शर्मा

ग्राफिक डिजाईनर
रजत जाखड़

स्वत्वाधिकारी

केम्ब्रिज मल्टी मीडिया के लिए प्रकाशक, मुद्रक रामेश्वरलाल जाट द्वारा केम्ब्रिज मल्टी मीडिया प्रा.लि. सी-565, सी-4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं सी-565, सी-4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर रोड़ जयपुर से प्रकाशित

संपर्क
संपादक
जयपुर टाइम्स (मासिक)
सी-588, सी-4सी स्कीम,
न्यू लोहा मण्डी रोड़
जयपुर-302013

E-mail
jaipurtimes2007@gmail.com

website
www.jaipurtimes.org

मो. 7014217770

मूल्य:- 100/- प्रति अंक
वार्षिक सदस्यता- 1251 (पोस्टल चार्ज सहित)

सुधी पाठकों के लिए जयपुर टाइम्स का विशेष संदेश

पंजाब में आई बाढ़:
एक राष्ट्रीय कर्तव्य की पुकार

पंजाब इस समय एक भयंकर आपदा से जूझ रहा है। लगातार बारिश और नदियों के उफान ने वहाँ के गाँवों, खेतों और शहरों को पानी में डुबो दिया है। किसानों की मेहनत से उगी फसलें नष्ट हो गई हैं, घर उजड़ गए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यह बाढ़ सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी और ज़िम्मेदारी का संदेश है।

प्राकृतिक आपदाएँ हमें बार-बार यह याद दिलाती हैं कि मनुष्य चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, प्रकृति के आगे उसकी सीमाएँ हैं। पंजाब की बाढ़ ने दिखाया कि कैसे पलभर में जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। यह समय आलोचना का नहीं, बल्कि एकजुट होकर सहायता का है।

बाढ़ प्रभावित लोग सिर्फ सरकार की ओर नहीं देख सकते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार राहत कार्य कर रही हैं, सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करे। कोई आर्थिक सहायता दे सकता है, कोई भोजन और कपड़े पहुँचा सकता है, तो कोई अपने समय और श्रम से स्वयंसेवक बनकर सेवा कर सकता है। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा असर डालते हैं।

आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शक्ति को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। युवा वर्ग इन साधनों का उपयोग कर राहत सामग्री जुटाने, जानकारी फैलाने और मदद पहुँचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। पारदर्शी क्राउड-फंडिंग, राहत शिविरों की जानकारी साझा करना और स्थानीय प्रशासन से समन्वय करना—ये सब कदम पीड़ितों तक मदद पहुँचाने को तेज़ और प्रभावी बना सकते हैं।

भारत एक विशाल परिवार है। जब किसी राज्य पर संकट आता है, तो उसका दर्द बाकी राज्यों को भी महसूस करना चाहिए। जैसे पहले के समय में भूकंप, सुनामी या कोविड महामारी के दौरान देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही पंजाब की इस आपदा को भी हमें राष्ट्रीय चुनौती मानना होगा।

पंजाब की बाढ़ केवल एक भौगोलिक क्षेत्र की त्रासदी नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी और अवसर है—मानवता को निभाने का अवसर। आइए, हम सब मिलकर यह संदेश दें कि जब-जब हमारे देशवासी मुसीबत में होंगे, तब-तब पूरा भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही सच्चा राष्ट्रधर्म है और यही मानवीय फर्ज़।

-प्रधान संपादक
रामेश्वरलाल जाट

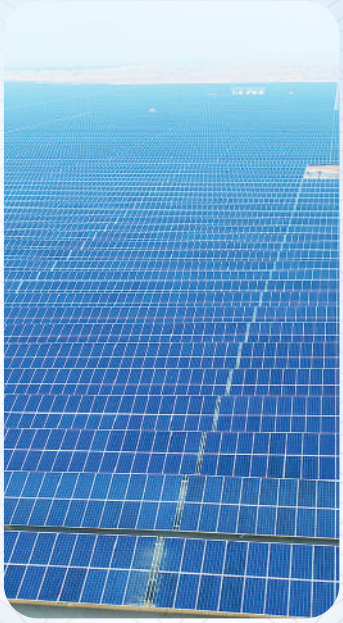

भजनलाल सरकार ने लिखी विकसित राजस्थान फिल्म की पटकथा, निर्माण शुरू

"अगस्त का महीना प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए बन गया वरदान, जयपुर को वंडरफुल हाई प्रोफाइल बिजनेस सिटी बनाने की तैयारी, 2030 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य, हर क्षेत्र और विभाग के लिए तैयार की कार्य योजना, हर साल कार्यों की होगी समीक्षा"

जयपुर। वैसे तो प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही ऐतिहासिक जन कल्याणकारी फैसलों और निर्णय को लेकर देश में सुर्खियों में रही है लेकिन पिछला अगस्त का महीना प्रदेश के 8 करोड लोगों के लिए उस समय वरदान बन गया, जब भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में अनेक ऐसे फैसले और निर्णय लिए गए, जिनके क्रियान्वयन के बाद निश्चित रूप से राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगस्त का महीना यूं तो भारत की आजादी के लिए और आजादी के बाद से ही पूरे देश के लिए खास माना जाता रहा है लेकिन पिछले अगस्त के महीने में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करके विकसित राजस्थान फिल्म की जो पटकथा लिखी और पटकथा लिखने के साथ ही फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है, उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि जब यह फिल्म प्रदर्शित होगी तो फिल्म देखने से लोगों को जो आनंद की अनुभूति होगी, उसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि यह फिल्म आजादी के बाद राजस्थान के विकास की ऐसी नजीर पेश करेगी, जो देश के अन्य राज्यों की सरकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वैसे इस फिल्म के लेखक डायरेक्टर और निर्देशक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही है इसलिए उम्मीद सबको यही है कि यह फिल्म बहुत जल्दी ही निर्धारित समय से पहले प्रदेश के 8 करोड लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में गुलाबी शहर जयपुर का शानदार फिल्मांकन किया गया है। जिसकी वजह से जयपुर को वंडरफुल हाई प्रोफाइल बिजनेस सिटी के रूप में पूरी दुनिया में अलग से पहचान मिलेगी। इस फिल्म में जब लोग जयपुर में टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर और दिल्ली के एम्स की तर्ज पर हाई प्रोफाइल उच्च कोटि का चिकित्सा इंस्टीट्यूट देखेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, वैसे तो जयपुर पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है लेकिन अब बनने जा रहे इस वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर और एम्स की तर्ज पर बनाने जा रहे रिम्स उच्च कोटि के मेडिकल इंस्टिट्यूट से टेक्नोलॉजी बिजनेस और मेडिकल में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है जो निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों के लिए तो खुशी के ऐतिहासिक पल है ही इसके अलावा विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम कहा जा सकता है।

प्रदेश के रेगिस्तान के जिले अब सौर ऊर्जा उत्पादन के बनने जा रहे हैं बड़े केंद्र

प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रदेश के उन जिलों जहां जमीन बंजर है, चारों तरफ रेगिस्तान है वहां की अत्यधिक गर्मी और वातावरण का सदुपयोग बिजली उत्पादन में करने जा रही है। इसके लिए जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में बंजर भूमि पर सोलर प्लांट और सोलर पार्क स्थापित किया जा रहे हैं, इसके लिए वहां किसानों को अपनी जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को इन सोलर प्लांट से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्य में किसान दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान जो अब से पहले फसल पैदा करते थे, अब बिजली उत्पादन करने लगे हैं। इस कार्य को प्रदेश की भजनलाल सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साफ कहते हैं कि राजस्थान का किसान अब बिजली उत्पादक बन रहा है और आने वाले दिनों में राजस्थान इन बिजली उत्पादक किसान के दम पर पूरे देश को बिजली बचेगा। इसकी वजह से एक तरफ जहां समुचित बिजली का उत्पादन होने से राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होगी तो दूसरी तरफ बिजली बेचने की वजह से किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भजनलाल सरकार ने फिलहाल 1280 हेक्टर बंजर भूमि में सोलर प्लांट और सोलर पार्क स्थापित करने जा रही है। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाले किसान को बिजली का कनेक्शन भी तुरंत दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जानकार लोगों का कहना है कि सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन का यह कार्य राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश के लिए वरदान बन रहा है, जहां पहले बंजर भूमि का कोई उपयोग नहीं होता था, वहां अब सोर ऊर्जा का उत्पादन करके बंजर भूमि से सोना पैदा किया जाने लगा है। जिसकी वजह से किसान मालामाल हो रहा है और राजस्थान सरकार जो महंगे दामों पर सालों से दूसरे स्टेट से बिजली का आयात करती है, उस पर भी अंकुश लगेगा, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी, यह बचत का पैसा प्रदेश के अन्य विकास कार्यों में संपादित हो सकेगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन होने से राजस्थान जब पूरे हिंदुस्तान को बिजली देगा तो इससे राजस्थान को प्रॉफिट भी होगा, यही वजह है कि प्रदेश के भजनलाल सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दिए हुए हैं।

RISING RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

भारत की शान म्हारा राइजिंग राजस्थान

क्रमबद्ध और सुनियोजित तरीके से विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग

भजनलाल सरकार ने 2030 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूरगामी सोच के आधार पर वर्तमान में कार्य योजनाएं तैयार की है। इन कार्य योजनाओं को तैयार करते समय वर्तमान की जरूरत का ख्याल रखने के साथ-साथ आगामी 20 से 25 साल की चुनौतियां एवं विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाएं तैयार की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी समस्या या चुनौती अचानक आकर खड़ी ना हो जाए, इसलिए भजनलाल सरकार ने पहले से ही पूरी प्लानिंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए बाकायदा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, सड़क, पानी, बिजली, सौर ऊर्जा, पर्यटन, टेक्नोलॉजी इत्यादि सभी क्षेत्रों में कार्य योजनाएं तैयार की गई है। इन कार्य योजनाओं को कैसे किस तरह से और कितनी अवधि में पूरा किया जाना, यह सब सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं हर साल इन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। अगर किसी योजना में काम की गति धीमी है और निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया है या किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। कुल मिलाकर सरकार पूरी प्लानिंग के तहत प्रदेश के विकास को गति देने को कृत संकल्प है, सरकार ने हर क्षेत्र में और हर विभाग में कार्य योजनाएं तैयार की है इसलिए एक भी क्षेत्र और एक भी विभाग विकास कार्यों से अछूता नहीं रहेगा।

अगस्त के महीने में भजनलाल सरकार ने लिए कई बड़े निर्णय

पिछले अगस्त के महीने में भजनलाल सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें जयपुर में 3500 करोड रुपए की लागत से बनने वाला वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली के एम्स की तर्ज पर जयपुर में ही उच्च कोटि का मेडिकल इंस्टिट्यूट, प्रदेश के रेगिस्तान इलाकों में सोलर पार्क और सोलर प्लांट की स्थापना करके सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना ताकि राजस्थान पूरे देश को बिजली बेच सके, प्रदेश में जिन हवाई पट्टी का कम उपयोग हो रहा है, वहां जमीन को अन्य हवाई गतिविधियों के लिए लीज पर देना, नगर निकायों की ओर से धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मीडिया संस्थान और अन्य कार्यों के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि डीएलसी की 25% दर पर उपलब्ध करवाना। राजस्थान विधानसभा के सेवा भर्ती नियमों और पदोन्नति के नियमों में संशोधन करके अधिकारियों, कर्मचारियों को, सुरक्षा गार्ड्स को राहत पहुंचाना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय और घोषणाएं जैसे अनेक निर्णय लिए गए। जिनसे प्रदेश के विकास को निश्चित रूप से पंख लगेंगे और जयपुर शहर जो अब तक ऐतिहासिक हेरीटेज सिटी के रूप में बड़े किलो, खूबसूरत महल और आकर्षक हेरिटेज बिल्डिंग के लिए दुनिया भर में माना जाता है, वह अब टेक्नोलॉजी और अत्यधिक सुख-सुविधाओं संपन वाले शहर बेंगलुरु, हैदराबाद की तरह नजर आने लगेगा।

टोंक रोड पर बनने वाले वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर से जयपुर को दुनिया भर में मिलेगी अलग पहचान

वैसे तो गुलाबी शहर जयपुर पर्यटन के मामले में दुनिया भर में विख्यात है लेकिन आने वाले 3 साल में जब जयपुर के टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, तब जयपुर एक अलग ही कलेवर में नजर आएगा क्योंकि इस वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर में 5 सितारा और चार सितारा दो होटल बनेंगे, यहां आईटी टावर स्थापित होंगे, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र, रेजिडेंशियल सुविधा, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंस रूम जैसे अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं के तमाम प्रबंध रहेंगे। इस भव्य और विशाल खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर का निर्माण दिल्ली की उस कंपनी से ही करवाया जा रहा है, जिसने दिल्ली में भारत मंडपम का निर्माण किया था। इस वर्ल्ड क्लास सेंटर से एक तरफ जहां जयपुर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो दूसरी तरफ यहां आए दिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग आयोजित होगी। बेंगलुरु और हैदराबाद शहर की तरह जयपुर भी विश्व स्तरीय सुख सुविधाओं वाली मॉडर्न सिटी के रूप में स्थापित होगा, जिसकी वजह से जयपुर की व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा, सरकार को इनकम होगी, पर्यटन में भी इजाफा होगा।

एम्स की तर्ज पर जयपुर में बनने वाले उच्च कोटि का मेडिकल इंस्टिट्यूट रिम्स प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में लेकर आएगा क्रांति

जयपुर में आगामी 2 साल में दिल्ली के एम्स की तर्ज पर हाई प्रोफाइल मेडिकल इंस्टिट्यूट रिम्स की स्थापना की जाएगी। यह इंस्टीट्यूट एक तरीके से प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई बड़ी क्रांति लेकर आएगा। यह ठीक दिल्ली के एम्स की तरह होगा, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान जैसे कार्य भी होंगे। इसमें हाई प्रोफाइल हॉस्पिटैलिटी की सुविधा होगी और इसके निर्माण से कहीं ना कहीं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को भी मरीजों की संख्या से राहत मिलेगी। क्योंकि सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़ी संख्या में रोजाना मरीज उपचार के लिए आते हैं, यहां राजस्थान के कोने-कोने से ही नहीं बल्कि उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्यों से भी यहां उपचार करने के लिए लोग आते हैं। इसलिए वर्तमान में इस अस्पताल पर मरीजों का जबरदस्त लोड है लेकिन जब यह उच्च कोटि का मेडिकल इंस्टिट्यूट शुरू हो जाएगा, तब एस.एम.एस. अस्पताल से मरीजों का लोड कम होगा, इसलिए मेडिकल इंस्टिट्यूट में फैकल्टी के निर्माण के लिए समिति गठित की

जाएगी। इस इंस्टिट्यूट से विश्व स्तर के डॉक्टर तैयार होंगे, जो प्रदेश, देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे और लोगों का बैटर उपचार करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे पसंद के ऑफिसर हैं सुधांशु पंत

"भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारों में अपने श्रेष्ठ कार्यों, नवाचारों और नए प्रयोगों से सबके पसंद के ईमानदार और कर्मठ अफसर माने जाते रहे, देश की पूरी आईएएस लॉबी में रखते हैं अपना अलग रुतबा, केंद्र और राजस्थान दोनों सरकारों के हमेशा प्रिय रहे"

जयपुर। देश की पूरी आईएएस लॉबी में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत का अपना एक अलग ही प्रभाव और रुतबा है। यह रुतबा अब से नहीं बल्कि कई सालों से है, ईमानदारी, वर्किंग स्टाइल, नवीन प्रयोग, नवाचारों, निर्णय लेने की क्षमता, टाइम पंक्चुअल, अनुशासन और ड्यूटी के प्रति इनके पूर्ण समर्पण भाव ने इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में ही नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं की नजरों में अब से नहीं बल्कि कई सालों से पसंदीदा अफसर बने हुए हैं। यही वजह है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की सरकारों में इन्हें बड़े-बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेवारी को इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया भी, केंद्र में भी इन्हें जब प्रतिनियुक्ति पर काम करने का मौका मिला तो वहां भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। देश में कोरोना की अवधि में केंद्र में स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने सेक्रेटरी पद पर रहते हुए जिस तरह से विभाग का श्रेष्ठ संचालन किया। उस समय कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने अनुभव, नवाचारों, और नवीन प्रयोगों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर जो उत्कृष्ट कार्य किया। उसी का नतीजा रहा की पूरी दुनिया में कोरोना मैनेजमेंट में भारत काफी आगे रहा, इस उपलब्धि को पीएम नरेंद्र मोदी आज तक नहीं भूले यही वजह है कि दिसंबर 2023 में जब राजस्थान में तत्कालीन मुख्य सचिव उषा शर्मा की रिटायरमेंट का समय आया तो उस समय आधा दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को लांघकर सुधांशु पंत को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। इसका कारण शासन सचिवालय के गलियारों में यह माना गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिम्मेवारी और काम को आसान बनाने और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के प्रयासों में मुख्य सचिव पद के लिए सुधांशु पंत सबसे काबिल और भरोसेमंद अफसर भाजपा के रणनीतिकारों को नजर आए। इसलिए इन्हें केंद्र से हाथों-हाथ रिलीव करके राजस्थान भेजा गया ताकि राजस्थान में भजनलाल सरकार को नई ऊर्जा और संबल मिल सके। यह निर्णय आज बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा है क्योंकि भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल की समीक्षा करें तो प्रदेश में पिछले 2 साल में कई बड़े ऐतिहासिक निर्णय और फैसले लिए गए, कई बड़े काम संपादित हुए जिनकी वजह से प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिली है और प्रदेश सरकार के काम की तारीफ प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देशभर में हो रही है। जिसका बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इन दोनों ही महत्वपूर्ण पदों पर ईमानदार, कर्मठ और साफ-सुथरी छवि के शख्स विराजमान हैं तो फिर सरकार के काम तो अच्छे होंगे ही।

सुधांशु पंत के प्रयासों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में आया क्रांतिकारी बदलाव

इसमें कोई संदेह नहीं, इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि पिछले 2 साल में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक क्रांतिकारी बदलाव आया। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली और व्यवहार में काफी बदलाव हुआ है, अधिकारियों और कर्मचारियों का ऑफिस समय पर आना, ऑफिस को समय पर छोड़ना, अनुशासित तरीके से ऑफिस में काम होना इत्यादि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आने लगा है। इस तरह का बदलाव नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है, यह जो नया माहौल सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है, इसका पूरा श्रेय मुख्य सचिव सुधांशु पंत को दिया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने जिस दिन मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली थी, उस दिन से ही सभी सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों से रोजाना नियमित रूप से संवाद करते हैं, उनसे उनके कामों की रिपोर्ट मांगते हैं, सभी सरकारी विभागों में फाइलों की पेंडेंसी का भी बारीकी से अवलोकन करते हैं, समय-समय पर खुद भी बिना बताए किसी भी दफ्तर में हालातों की जानकारी लेने के लिए अचानक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े सभी छोटे-बड़े अधिकारी अपने कार्य और अपनी ड्यूटी को लेकर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर और चौकस रहने लगे हैं क्योंकि उन्हें अब अपने काम की रिपोर्ट नियमित रूप से अपने से ऊपर अधिकारी तक पहुंचानी पड़ती है। पहले, इतनी पाबंदियां नहीं थी लेकिन उनसे सवाल-जवाब पूछा जाता है। अब उनसे अनुपस्थित रहने का कारण पूछा जाता है, अब उनसे ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है तो उसके बारे में भी नियमित रूप से पूछा जाता है, इसलिए सभी छोटे-बड़े अधिकारी अपने रोजाना के ऑफिशियल वर्किंग काम को लेकर काफी गंभीर रहने लगे हैं, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में काफी नयापन और बदलाव आया है जिसकी वजह से प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिली है।

वित मामलों के विशेषज्ञ हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांशु पंत वित्त संबंधी मामलों के अच्छे जानकार हैं, किसी भी संस्था या विभाग की कैसे और किस तरह से इनकम बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से आर्थिक स्त्रोत पैदा किया जा सकते हैं और पैसों का कैसे और किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, इन सब की बहुत अच्छी जानकारी है। इसलिए राजस्थान में वित्त संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, जिसके कारण वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 में राजस्थान सरकार की ओर से सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त पद पर रहने के दौरान प्राधिकरण की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। इनके प्राधिकरण के आयुक्त पद पर रहने के दौरान शहर में जेडीए की ओर से कई बड़े काम शुरू किए गए। जेडीए की ओर से विकसित की गई कॉलोनी में सड़क, पार्क, सेक्टर रोड, सामुदायिक भवन इत्यादि का खूब निर्माण करवाया गया। एक से एक सौगातें जयपुर के लोगों को दी गई, जिसकी वजह से चारों तरफ जेडीए के काम की खूब चर्चा हुई। इसी तरह से नगरीय विकास विभाग के सचिव पद पर रहने के दौरान भी प्रदेश की नगर निकायों के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने कई तरह के नवीन प्रयोग और नवाचार किये। इसी तरह से खान और पेट्रोलियम विभाग में भी इन्होंने सचिव पद पर रहते हुए खान विभाग के कामकाज को काफी गति दी जिससे काफी हद तक खान विभाग की कार्यशैली और कामकाज में सुनिश्चता आ गई थी, जिसके कारण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में खान विभाग ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस तरह से सुधांशु पंत जिस भी विभाग मे पोस्टेड रहे, उस विभाग का श्रेष्ठ प्रबंधन करके उन्होंने विभाग को एक नए कलेवर में डालने का प्रयास किया तो दूसरी तरफ विभाग की उपलब्धि और गतिविधियों को देखकर प्रदेश की जनता को भी काफी राहत मिली और सरकारों ने भी उनके कामकाज को काफी सराहा।

जयपुर में सबसे अधिक समय तक महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टेड रहे मुख्य सचिव सुधांशु

मुख्य सचिव सुधांशु जयपुर में सबसे लंबे समय तक अलग-अलग पदों पर पोस्टेड रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के शुरू के काल में सुधांशु जयपुर में एसडीएम पद पर रहे बाद में जयपुर के कलेक्टर पद पर भी रहे। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद पर रहे और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद पर सुधांशु पंत लंबे समय तक पोस्टेड रहे। फिर शासन सचिवालय में कई विभागों में बड़े पदों पर रहे, खान और पेट्रोलियम विभाग, जलदाय विभाग, वन विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कमिश्नर पद पर नियुक्त रहे कुल मिलाकर जयपुर में इन्होंने सबसे अधिक समय तक नौकरी की। हालांकि जयपुर के अलावा जैसलमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू जिलों के कलेक्टर पद पर भी रहे। केंद्र में बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग विभाग के सेक्रेटरी रहे तथा स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी रहे। इस तरह से अब तक की सरकारी नौकरी में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण विभागों में बड़े पदों पर नियुक्त रहने के दौरान इन्होंने हर जगह श्रेष्ठ प्रदर्शन करके केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का दिल जीता, कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल के बड़े नेता भी उनकी कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल और ईमानदारी से काफी प्रभावित हैं।

राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों जगह कई बड़े बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई

प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अपनी इस लंबी सरकारी सर्विस के दौरान इन्होंने राजस्थान में नौकरी में लंबा समय बिताया है। कई जिलों के कलेक्टर रहने के अलावा प्रदेश के सभी बड़े डिपार्मेंटों में बड़े पदों पर रहे इसलिए चाहे प्रदेश में किसी सरकार की ओर से बजट की रूपरेखा तैयार करने का मामला हो या फिर राजस्थान विधानसभा में कोई बिल प्रस्तुत करने का मामला हो, इस तरह के मामलों में चाहे प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सभी सरकारों ने सुधांशु पंत से सलाह लेती रही। प्रदेश में बजट चाहे किसी भी अधिकारी के सान्निध्य में तैयार किया जाता रहा हो, लेकिन हर बजट में सुधांशु पंत की सलाह को प्रमुखता से लिया जाता रहा। कई बड़े बिलों का ड्राफ्ट तैयार करने में सुधांशु पंत की बड़ी भूमिका रही। केंद्र सरकार में भी स्वास्थ्य विभाग में सचिव पद पर रहने के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों का ड्राफ्ट सुधांशु पंत ने ही तैयार किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का बिल का ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था, बाद में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के रूप में स्थापित हो गया। वर्तमान में भी राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनकी भूमिका तैयार करने में सुधांशु पंत की ही प्रमुख भूमिका है क्योंकि सुधांशु पंत के बारे में कहा जाता है कि इन्हें जनता से जुड़े विषयों और जनता से जुड़ी समस्याओं की बहुत ही बारीकी से जानकारी है। शहरों और गांव दोनों जगह की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद हर विषय की बारीकी से जानकारी है। इसलिए चाहे बजट तैयार करने की बात हो या फिर जनता को राहत देने के लिए किसी बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो, हर सरकारों ने सुधांशु पंत की सलाह को हमेशा तवज्जों दी।

अपनी लंबी सरकारी नौकरी में कभी भी राजनीतिक प्रेशर में नहीं आए मुख्य सचिव सुधांशु

जानकार लोगों का कहना है की मुख्य सचिव सुधांशु कभी भी किसी भी राजनीतिक प्रेशर में नहीं आते। अपनी लंबी सरकारी नौकरी के दौरान एक भी अवसर ऐसा नहीं आया, जब उन्होंने कभी किसी राजनेता या किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में आकर नियम और कानून के खिलाफ काम किया हो। जानकार लोगों का कहना है कि वैसे तो कोई राजनेता उन्हें अपने किसी काम के लिए फोन करता ही नहीं है क्योंकि वह यह जानता है कि यह अधिकारी अपने प्रेशर में नहीं आएगा और अगर भूले-भटके इन्हें अपने काम के लिए कोई प्रेशर डालें तो किसी के प्रेशर में भी नहीं आते, हमेशा ईमानदारी से और बिना किसी राजनीतिक प्रेशर में आए, इन्होंने अब तक नौकरी की है और अब मुख्य सचिव की भूमिका में भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। यही वजह रही कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी काफी पसंद के अधिकारी रहे, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी काफी पसंद के अधिकारी रहे और अब भजनलाल शर्मा के काफी पसंद की अधिकारी माने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में तो बहुत पहले से ही कर्मठ और ईमानदार शरीर के रूप में छाए हुए थे ही तभी तो इन्हें राजस्थान में मुख्य सचिव की कुर्सी पर बिठाया गया।

सरकारी फाइलों के निस्तारण को लेकर शुरू से ही काफी गंभीर रहे हैं मुख्य सचिव

प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु वर्किंग स्टाइल काफी गजब की है। अपनी लंबी सरकारी सर्विस के दौरान जिस भी विभाग में रहे, उस विभाग में अपनी टेबल पर आने वाली प्रत्येक फाइल के निस्तारण को लेकर हमेशा गंभीर रहे और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फाइल को निपटा कर आगे फॉरवर्ड करने में विश्वास रखते थे। अगर किसी फाइल में कोई कानूनी अड़चन आ रही हो तो उसका रास्ता निकालने के लिए भी गंभीरता से प्रयास करते, चाहे कोई फाइल छोटे विषय से संबंधित हो या फिर कोई फाइल महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो, हर फाइल को हमेशा गंभीरता से लेते और निश्चित समय में ही फाइल का निस्तारण करके ही मानते। इसके लिए उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी साफ निर्देशित किया हुआ था कि उनके दफ्तर में कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए और अब मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी हाथ में लेने के बाद भी उनका वर्किंग स्टाइल वैसा ही है। अब भी रोजाना बड़ी संख्या में फाइलों का निस्तारण करके आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, किसी भी फाइल को अपनी टेबल पर अधूरी छोड़ने में विश्वास नहीं रखते। जब तक फाइल का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे उस फाइल के पत्रों को टटोलत ही रहते हैं, सुधांशु पंत ने सभी सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों को भी यह साफ निर्देशित किया हुआ है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि किसी भी फाइल को बेवजह अलमारी में ना रखें, अगर फाइल की निस्तारण में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में अपने बड़े अधिकारी से चर्चा करें लेकिन फाइल का निस्तारण करके, उसे हर हाल में आगे फॉरवर्ड करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सच्चे सारथी बने हैं मुख्य सचिव सुधांशु

मुख्य सचिव सुधांशु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सच्चे सारथी बने हुए हैं और काफी हद तक मुख्यमंत्री के काम के बोझ को भी हल्का किए हुए हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच आपस में जोरदार समन्वय तालमेल बना हुआ है, मुख्य सचिव सभी सरकारी विभागों के कामकाज और गतिविधियों की रिपोर्ट का संकलन करके उन्हें मुख्यमंत्री तक भिजवाते रहते हैं और यह बताते रहते हैं कि कौन सा विभाग अच्छा काम कर रहा है और कौन से विभाग की काम की रफ्तार ठीक नहीं है और कौन-सा विभाग काम में पिछड़ा हुआ है। इन सब के बारे में नियमित रूप से वास्तविक जानकारी मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तक भिजवाते रहते हैं। चाहे बजट तैयार करने की बात हो या फिर कोई जनकल्याणकारी योजना बनाने की बात हो या फिर कोई नया बिल बनाने की बात हो या फिर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर करने की बात हो या फिर राजस्थान सरकार के किसी दूसरे स्टेट से विवाद के विषय हो या फिर केंद्र सरकार से फंडिंग का मामला हो, इन तमाम महत्वपूर्ण विषय और मुद्दों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य सचिव से गंभीरता से बातचीत करके ही फाइनल डिसीजन करते रहे हैं। भले ही भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हो, पहली बार मुख्यमंत्री बने हो लेकिन लंबे समय से प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी में संगठन में बड़े पद पर रहने के दौरान इन्होंने सुधांशु पंत की वर्किंग स्टाइल और उनकी ईमानदारी को नजदीकी से देखा है, इसीलिए हर छोटे-बड़े विषय पर मुख्य सचिव की सलाह को भजनलाल शर्मा ने हमेशा प्राथमिकता दी है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम को मुख्य सचिव ने काफी हद तक आसान और सरल बना दिया है।

भाजपा के संकल्प पत्र और बजट के वादों को पूरा करवाने में सुधांशु पंत की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के सभी मंत्री खुलकर दावा करते हैं कि सरकार ने अपनी बजट की घोषणाओं और भाजपा के संकल्प-पत्र के अधिकांश वादों को पूरे कर लिये है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों कि इस बात को गलत भी नहीं बताया जा सकता। निश्चित रूप से भाजपा के संकल्प-पत्र के अधिकांश वादे भजनलाल सरकार ने पूरे कर दिए हैं और बजट की घोषणाओं का क्रियान्वयन भी बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन इतनी तेज रफ्तार से यह जो काम हो रहा है, इसके पीछे मुख्य सचिव सुधांशु की तीसरी आंख है। अपनी इस तीसरी आंख से मुख्य सचिव सभी सरकारी विभाग के कामकाज का नियमित रूप से अपडेट लेते रहते हैं। सभी सरकारी विभाग के उच्च अधिकारी से बजट की घोषणाओं और संकल्प पत्र के वादों के क्रियान्वयन का भी फीडबैक लेते रहते हैं और अगर फीडबैक में उन्हें कोई कमी या लापरवाही किसी भी विभाग में नजर आती है तो फटकार लगाने में भी पीछे नहीं रहते यही वजह रही की एक तरफ संकल्प-पत्र और बजट घोषणा के वादों को पूरा करने में संबंधित विभाग शुरू से ही अलर्ट मोड पर रहा तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी सरकारी विभागों के साथ नियमित रूप से अपना संपर्क बनाकर रखा है। कभी विभाग के अधिकारियों से बैठक करते हैं तो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अधिकारियों से बातचीत करके उनसे विभाग के कामकाज को लेकर सवाल जवाब करते हैं। इसके अलावा विभाग के कामकाज का आकलन भी करते हैं और उन्हें अपनी ओर से टिप्स और दिशा-निर्देश भी देते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि अभी भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल भी पूरे नहीं हुए लेकिन संकल्प-पत्र के अधिकांश वादों को सरकार ने पूरा कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है, इसके लिए मुख्य सचिव को पूरा श्रेय दिया जा सकता है।

प्रदेश के सभी छोटे-बड़े अधिकारियों की वर्किंग पॉवर और उनके व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ है सुधांशु

मुख्य सचिव सुधांशु की गिनती ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में होती है। सरकारी नौकरी में लंबा समय राजस्थान में बिताया है, इसलिए इन्हें राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वर्किंग पॉवर, कार्यशैली और उनके व्यवहार की बारीकी से जानकारी है। सुधांशु यह जानते हैं कि कौन-सा अधिकारी किस विभाग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त साबित होगा, उन्हें एक-एक अधिकारी की योग्यता और अनुभव का अच्छी तरह से आभास है। इसलिए जब प्रदेश में बड़े अधिकारियों के तबादला करने की बात आती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तबादलों के बारे में भी कहीं ना कहीं मुख्य सचिव से बात जरूर करते हैं। जानकार लोगों का कहना है कि मुख्य सचिव सुधांशु यह जानते हैं कि उनसे जयपुर को ही नहीं बल्कि दिल्ली को भी काफी उम्मीद है। वह यह भी जानते हैं कि उनसे वरिष्ठ आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों को लांघकर उन्हें इस पद पर बिठाया गया। इसलिए उनके दिल में हमेशा यही रहता है कि उनका कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में राजस्थान में अब तक सर्वश्रेष्ठ रहे इसलिए वे अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। शासन सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में तो बैठकर सरकारी कामकाज निपटाते हैं ही इसके अलावा अपने सरकारी आवास पर भी देर रात तक फाइलों का निस्तारण करते रहते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह से लेकर देर रात तक सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी कामकाज में खुद को व्यस्त रखते हैं ठीक उसी तरह से मुख्य सचिव सुधांशु दिन-रात कड़ी मेहनत करके प्रदेश भजनलाल सरकार के कामकाज को गति देने में की जान से जुटे हुए हैं।

छापामार मुख्य सचिव माने जाने लगे हैं सुधांशु

जब से सुधांशु पंत ने मुख्य सचिव की जिम्मेवारी संभाली है तब से लेकर अब तक इन्होंने कई बार अलग-अलग सरकारी विभागों के दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने के समय की जांच पड़ताल की। दफ्तरों में फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को बारीकी से देखा, हाजरी रजिस्टर का अवलोकन किया और दफ्तर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल जवाब किया इसलिए अब प्रदेश के सभी छोटे-बड़े सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल और दिमाग में यही डर बना रहता है कि न जाने कब मुख्य सचिव यहां पर जांच पड़ताल के लिए आ जाएं। इसलिए सरकारी दफ्तर में कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारी के समय पर आने जाने की प्रक्रिया काफी हद तक सुधरी है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई मुख्य सचिव निरंतर सरकारी विभागों में अचानक जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाता हो। पहले इस तरह के बहुत कम मामले होते थे, मुश्किल से कोई मुख्य सचिव अपनी नियुक्ति के कार्यकाल में एक या दो दफ्तर में जाकर मोटे रूप से अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ कर लिया करता था लेकिन सुधांशु ने अब तक कई विभागों में खुद जाकर जांच पड़ताल की है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर नगर निगम हेरिटेज जैसे अनेक विभागों में इन्होंने मौके पर जाकर कामकाज की प्रक्रिया को बारीकी से देखा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के कार्यालय में तो अब तक दो बार मौके पर जाकर कामकाज का निरीक्षण कर चुके हैं। इसके अलावा शासन सचिवालय के विभिन्न सरकारी विभागों में भी नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्य सचिव कि इस छापामार कार्रवाई की वजह से वे अधिकारी और कर्मचारी जो समय पर नहीं आया करते थे और अपनी मनमानी किया करते थे, वह अब समय पर दफ्तर आने लगे हैं और समय पर ही तब तक छोड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी विभागों के कामकाज में नयापन जरूर नजर आने लगा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु में है कई समानताएं

जानकार लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु में कई समानताएं हैं और इन समानताओं की वजह से ही दोनों के बीच बहुत अच्छा वर्किंग तालमेल बना हुआ है। जिसका फायदा राजस्थान की जनता को तो मिल ही रहा है, इसके अलावा राजस्थान का विकास भी तेज गति से संपादित हो रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि भजनलाल शर्मा और सुधांशु दोनों ब्राह्मण बिरादरी के हैं, दोनों ही साफ-सुथरी और ईमानदार छवि के शख्सियत है। दोनों ही 24 घंटे में 18 से 20 घंटे सरकारी कामकाज में खुद को व्यस्त रखते हैं, दोनों ही ईमानदार हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी भरोसेमंद और विश्वास-पात्र बने हुए हैं। दोनों ही यह अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार से जुड़े बड़े नेता उनसे काफी उम्मीद करते हैं, दोनों ही ग्रामीण और शहरी इलाकों की समस्याओं को ही नहीं जानते बल्कि ग्रामीण और शहरी लोगों की जीवन शैली को भी अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों ही यह भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसे बुनियादी विषयों पर ज्यादा काम करना होगा। यही वजह है कि भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में पानी और बिजली के क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। पानी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हुए, जिसकी वजह से पानी के क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट के काम जारी हैं और इन प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के जो समझौते हुए थे उनमें प्रत्येक समझौते को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों गंभीरता से कार्य कर रहे है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा और सुधांशु दोनों के विचार और आचरण एक हैं दोनों काम के प्रति समर्पित है और दोनों गरीब को गणेश मानकर सेवा करने के संकल्प के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसीलिए भजनलाल सरकार के कामकाज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करनी पड़ी।

फिर से प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत जोरों से सक्रिय

अपनी कौन-सी प्लानिंग के तहत अशोक गहलोत फिर से पुराने रंग में आने लगे हैं नजर?

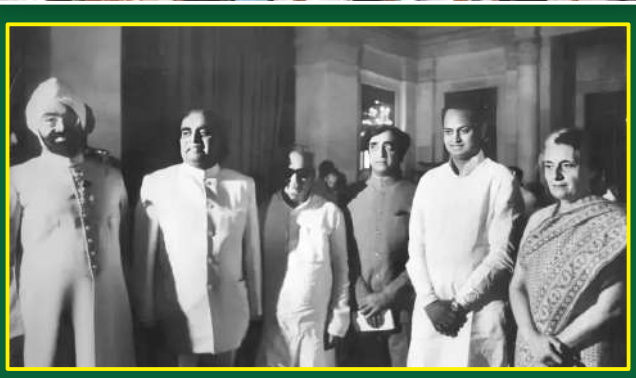

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए हैं। गहलोत के पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ प्रदेश में दौर हो रहे हैं। कई जगह पर जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ-साथ सभाओं को भी संबोधित किया है, गहलोत के अचानक तेजी से सक्रिय होने की सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी में हो रही है। कांग्रेस जनों में यह भी चर्चा सुनने को मिल रही है कि क्या कोई बड़ी विशेष प्लानिंग के तहत गहलोत ने फिर से मोर्चा संभाला है, अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि गहलोत प्रदेश की राजनीति में किस लेवल तक अपनी सक्रियता को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस पार्टी में उनकी यह सक्रियता आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, लेकिन इतना जरूर है गहलोत पिछले कुछ दिनों से अपने पुराने रंग में नजर जरूर आ रहे हैं, बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर में गहलोत अपने समर्थक नेताओं से जिस तरह से मुलाकात कर रहे है उससे कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अब इन सवालों के जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि अशोक गहलोत के पास ही हैं, हालांकि गहलोत समर्थक नेताओं में गहलोत की सक्रियता से नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है। लेकिन गहलोत समर्थक इस बात को लेकर भी चिंता में है कि गहलोत की अब पहले की तरह पार्टी के दिल्ली दरबार में ज्यादा एप्रोच नहीं रह गई है लेकिन फिर भी अब अचानक गहलोत की सक्रियता बढ़ने से गहलोत के समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है अपनी कोई विशेष बड़ी प्लानिंग के तहत गहलोत फिर से कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूत जड़ों को ढूंढ रहे हो। लेकिन बात कुछ भी हो गहलोत की सक्रियता ने कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी रणनीतिकारों की बेचैनी को बढ़ा दिया है।

कांग्रेस के बड़े नेताओं में अब भी समन्वय और तालमेल की कमी

राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में अब भी आपस में समन्वय और तालमेल की कमी साफ दिख रही है, अशोक गहलोत जहां राजस्थान में अपनी अलग से फील्डिंग जमाने में लग रहे हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट शुरू से ही अपने स्तर पर अपनी लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस पार्टी में और प्रदेश की जनता में अपने प्रभाव को लगातार मजबूत करने की कोशिश में युद्ध स्तर पर बहुत पहले से ही जुटे हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रहे, पिछले कुछ महीनो से संगठन में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां भी हुई है। लेकिन गहलोत और सचिन पायलट दोनों से अलग डोटासरा अपने स्तर पर पार्टी के संगठन का संचालन कर रहे हैं तो राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच भी पहले की तरह आपस में तालमेल और समन्वय नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा पिछले गहलोत सरकार में मंत्री रहे कुछ नेता अब भी गहलोत की पैरवी कर रहे हैं तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने सचिन पायलट की ओर अपना रुख किया है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, इसलिए राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक मंच पर दिखाई नहीं देना कांग्रेस पार्टी के लिए अब भी परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जोरदार तरीके से स्थिति दिखा रहे हैं गहलोत

पिछले कुछ दिनों से अशोक गहलोत अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी अपने संदेशों के माध्यम से एक तरफ जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने इन संदेशों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का टच हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, रोजाना कई मामलों को लेकर गहलोत ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि सभी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के तहत अपनी बातें रख रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर भी अशोक गहलोत की उपस्थित आज-कल दिखती है। गहलोत जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपनी प्रतिष्ठा को कांग्रेस पार्टी में और प्रदेश की पब्लिक में बरकरार रख सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से गहलोत रोजाना अलग-अलग विषयों पर अपनी बातें कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी में गहलोत के विरोधी नेताओं को तो बेचैन किए हुए है ही इसके अलावा भाजपा के लिए भी गहलोत का सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से उपस्थित रहना चिंता का विषय बना हुआ है।

गहलोत, पायलट के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं या डोटासरा के लिए

राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस पार्टी की गलियारों में चर्चा हो रही है कि अशोक गहलोत अचानक इतनी सक्रिय क्यों हुए, क्या गहलोत अपनी इस सक्रियता से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुनौती देने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं या फिर सचिन पायलट के लिए रास्ते कठिन कर रहे हैं या फिर अपनी इस सक्रियता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार को यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी में पकड़ अब भी कमजोर नहीं हुई है, बात चाहे कुछ भी हो गहलोत जो भी काम करते हैं बिल्कुल चुपके से अपनी पूरी प्लानिंग के तहत काम की शुरुआत करते हैं और जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रयास करते रहते हैं, इसलिए उनका इस तरह से अचानक सक्रिय होना निश्चित रूप से सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तो आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके अलावा भाजपा के लिए भी यह चिंता का विशेष जरूर बन सकता है क्योंकि अशोक गहलोत लगातार प्रदेश की भजनलाल सरकार को कई मामलों पर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से तो कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं इसके अलावा सार्वजनिक मंच और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भी भजनलाल सरकार से सवाल जवाब करते रहते हैं।

शहीद स्मारक पर एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा

पिछले दिनों जयपुर के शहीद स्मारक पर एनएसयूआई की ओर से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट और उनके समर्थक नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता शामिल नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और गोविंदसिंह डोटासरा जैसे नेता शामिल नहीं हुए, इसके अलावा पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सांगानेर से दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र भारद्वाज, यह दोनों ही नेता जो पहले राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, यह दोनों नेता भी एनएसयूआई के प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसलिए पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं की ओर से एनएसयूआई के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को लेकर भी कांग्रेस जनों में चर्चा होती रही, कांग्रेस जनों में आपस में यह चर्चा सुनने को मिली कि एक तरफ जहां सचिन पायलट प्रदर्शन में पानी की बौछारें खा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, कुछ लोग यह भी कह रहे थे, कि हो सकता है सचिन पायलट के बेहद नजदीक और भरोसेमंद नेताओं की ओर से यह प्रदर्शन किया गया था और सचिन पायलट जब खुद इस प्रदर्शन में अगुवाई कर रहे थे, शायद इस वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में नहीं आए या फिर ऐसा भी हो सकता है, एनएसयूआई के रणनीतिकारों ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं को इस प्रदर्शन में बुलाया ही नहीं हो, बात कुछ भी हो लेकिन सीनियर नेताओं के इस कार्यक्रम में नहीं आने की वजह से राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में आपस में टकराव के हालात जरूर बने हुए हैं, भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में अच्छे संबंध होने की बात कह रहे हो लेकिन अंदर से इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद जरूर है।

आखिर कब तक गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के सीनियर नेताओं की आपस की लड़ाई से जूझते रहेगें

हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पिछले दिनों अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया लेकिन इन 5 साल में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के दो बड़े सीनियर नेताओं के आपस की लड़ाई से जूझते रहे, जिसकी वजह से डोटासरा पिछली गहलोत सरकार के समय तो संगठन में नियुक्तियां ही नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि पिछली गहलोत सरकार के समय राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दो बड़े गुटों में बटे हुए थे इसकी वजह से संगठन में भी नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आधे-अधूरे संगठन के सहारे ही उन्होंने राजस्थान कांग्रेस का संचालन किया लेकिन यह तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने आधे-अधूरे संगठन से भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छी तरह से संचालन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन जुलूस और रैलियां आयोजित करके राजस्थान कांग्रेस की उपस्थिति को दमदार तरीके से राजस्थान में दिखाते रहे लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अब भी राजस्थान कांग्रेस में सीनियर नेताओं के बीच आपस में तालमेल और समन्वय नहीं बन पाया है। इसकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कई बड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई है, हालांकि प्रदेश में आने वाले महीनों में नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा इन चुनाव के मध्य नजर पार्टी के संगठन में पार्टी हाई कमान के निर्देश पर नियुक्तियां भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अब भी राजस्थान कांग्रेस में बड़े नेताओं की लड़ाई बरकरार है। इसकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं पार्टी का ठीक तरह से संचालन करने में परेशानी तो उठानी पड़ रही है।

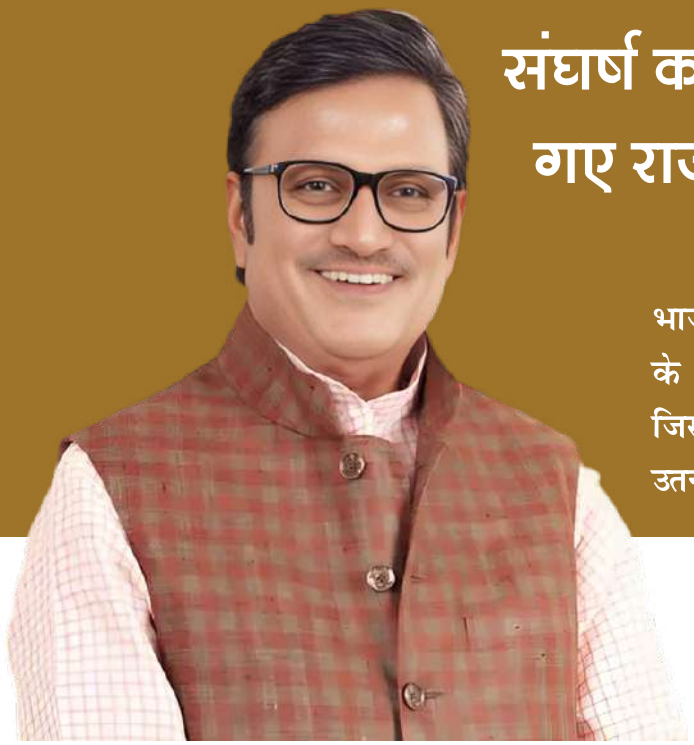

संघर्ष का दूसरा नाम 'राजेंद्र राठौड़', बन गए राजस्थान भाजपा के दबंग योद्धा

" आरएएस अधिकारी का बेटा जो बन गया भाजपा की आवाज, ऐसा प्रखर वक्ता जिसे सुनने के लिए सदन में भी विधायक रहते हैं उत्सुक, जिसकी जितनी संघर्ष की कठिन गाथा उसकी उतनी ही है बेमिसाल सफलता की गाथा "

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आजकल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के सदस्य भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को निश्चित रूप से मिस कर रहे हैं क्योंकि 1990 के बाद यह पहली बार है जब राठौड़ राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए राठौड़ की भाषण शैली, उनके बोलने का अंदाज, हर विषय पर तथ्यात्मक तरीके से पक्ष रखना और बीच-बीच में व्यंग्य कस देना जैसी उनकी हर अदा उन्हें सदन में सबसे अलग राजनेता बना देती थी। जिस पर सदन में हर किसी की निगाहें टिकी रहती थी और हर कोई राजेंद्र राठौड़ को सुनने के लिए बेताब रहता था लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय मिलने की वजह से राठौड़ अभी राजस्थान विधानसभा में नहीं पहुंच पाए लेकिन उनकी व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक हैसियत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। उनका जो रुतबा पार्टी में पहले बना हुआ था, वह रुतबा आज भी बरकरार है, वह आज भी राजस्थान भाजपा के छोटे-बड़े सभी नेताओं में काफी लोकप्रिय हैं, अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र तारानगर और चुरु की पब्लिक के दिलों पर तो राज करते ही हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज के छोटे-बड़े सभी नेताओं में उनकी पकड़ अब भी पहले की तरह ही है। राजस्थान भाजपा के दबंग, प्रखर वक्ता और जोशीले राजनेताओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल है, जिन्होंने खुद को एक श्रेष्ठ मंत्री के रूप में साबित करके दिखाया है, इसके अलावा पार्टी के कुशल रणनीतिकारों में शीर्ष

पर है और इनकी राजनीतिक कुशलता से भाजपा का दिल्ली दरबार भी बहुत पहले से परिचित है। इसलिए अब इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी तो राजेंद्र राठौड़ को किसी बड़े पद पर राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है और उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है।

शुरु के दो चुनाव हारने के बाद वर्ष 1990 से 2018 तक लगातार विधायक चुने गए

राजेंद्र राठौड़ ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1980 में जनता दल के टिकट से लड़ा था लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, 1985 में जनता दल ने फिर उन्हें टिकट दिया लेकिन इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1990 में फिर उन्हें जनता दल ने टिकट दिया और इस बार उन्होंने चुनाव जीता लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की और फिर 1993 से 2018 तक लगातार विधायक चुने गए। इस दौरान तारानगर और चुरु विधानसभा क्षेत्र से चुने गए लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव तारानगर से हार गए। बड़ी बात यह है कि राजस्थान विधानसभा के इतने लंबे सफर में राजेंद्र सिंह राठौड़ प्रदेश में भैरवसिंह शेखावत सरकार में भी मंत्री रहे और वसुंधरा राजे के दोनों शासनकाल में मंत्री रहे, बाद में पिछली गहलोत सरकार में गुलाबचंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ को सदन में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी मिली। जानकार लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था हालांकि हालांकि भैरोंसिंह शेखावत तीन बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्हें समर्थन के लिए निर्दलीय विधायकों की ओर देखना पड़ा था और इस काम में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बार बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से कई निर्दलीय विधायकों को भैरोंसिंह शेखावत सरकार का समर्थन देने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद से ही राजेंद्र राठौड़ का राजस्थान भाजपा में जबरदस्त प्रभाव होने लगा था, हालांकि उस समय राजस्थान भाजपा में कई सीनियर नेता थे, जो राजेंद्र राठौड़ से उम्र में काफी बड़े थे लेकिन तमाम सीनियर नेताओं के बीच राजेंद्र राठौड़ ने अपना जोरदार रुतबा कायम कर लिया था। जिसकी वजह से भैरवसिंह शेखावत की राठौड़ को काफी पसंद किया करते थे। बाद में 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो 2003 से 2008 तक राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा सरकार में नंबर दो मंत्री माने जाते थे।

राजस्थान विधानसभा में पार्टी के विधायकों को एकजुट बनाए रखने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई

जानकार लोगों का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ जब तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे तब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन के अंदर और सदन के बाहर एकजुट बनाए रखने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई, चाहे बीजेपी के विधायक विपक्ष की गैलरी में बैठे हो या फिर सत्ता पक्ष में हो राठौड़ ने हमेशा सदन में पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए विधायकों को एकजुट रखा। अगर बीजेपी को विपक्ष की भूमिका मिली तो उन्होंने सरकार को कैसे और किस तरह से घेरना है और किन मुद्दों को लेकर घेरना है, इन सब की रणनीति तैयार करने में राठौड़ हमेशा आगे नजर आए। भले ही उन्हें विपक्ष के नेता पद की भूमिका काफी विलंब से मिली हो लेकिन सदन में उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा के विधायकों को एकजुट रखा ताकि सत्ता पक्ष की ठीक तरह से घेराबंदी की जा सके। जब वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया विपक्ष के नेता रहा करते थे तब भी विधानसभा में पार्टी से जुड़े तमाम कामों की जिम्मेदारी राठौड़ ही संभालते थे, राठौड़ की राय को ही सर्वोपरि माना जाता था और राठौड़ ही विधायकों से नियमित रूप से संपर्क में रहकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहते थे। इसलिए राजस्थान विधानसभा में भाजपा की आवाज को बुलंद करने में राठौड़ हर तरह से हमेशा आगे रहे।

पार्टी के नए विधायक राठौड़ से हमेशा रहे प्रभावित

वर्ष 1990 से 2018 तक भाजपा के विधायक रहने के दौरान राजस्थान विधानसभा में हमेशा बड़ी संख्या में भाजपा के नए विधायक भी चुनकर आए, वसुंधरा राजे के पहले शासन काल और वसुंधरा राजे के दूसरे शासनकाल में भी कई नए विधायक चुनकर आए। इस दौरान गहलोत सरकार के शासनकाल में भी भाजपा के कई नए विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे और नए विधायकों को राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से अवगत करवाने के लिए तथा नए विधायक कैसे और किस तरह से सदन में अपनी बात रखें, इन सब के बारे में राठौड़ हमेशा नए विधायकों को सलाह और राय देते रहे और उन्हें पूरी तरह से गाइड करते रहे जिसकी वजह से नए विधायकों पर भी राजेंद्र राठौड़ का हमेशा अच्छा प्रभाव रहा और नए विधायक भी राजेंद्र राठौड़ का काफी सम्मान करते थे। इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी के नए विधायक भी कई बार राजेंद्र राठौड़ से आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन लेते रहते थे जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नए विधायक राठौड़ को श्रेष्ठ राजनेता के रूप में मानते थे और उनका भाषण भी बड़े ध्यान से सुना करते थे। कई नए विधायकों ने राठौड़ से काफी कुछ सीखा भी और राठौड़ ने भी कभी भी नए विधायकों के सामने खुद को वरिष्ठ नहीं माना उन्हें अपना छोटा भाई मानकर उनका मार्गदर्शन करते रहे।

राजस्थान विश्वविद्यालय को आज तक राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसा छात्रसंघ अध्यक्ष नहीं मिला

राजस्थान विश्वविद्यालय के गलियारों में भी अक्सर यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि राजेंद्र रोड राठौड़ जैसा छात्र संघ अध्यक्ष आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाया है, प्रदेश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस इन दोनों ही दलों में कई बड़े नेता ऐसे हैं जो पहले राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे उस समय राठौड़ ने छात्र हितों की रक्षा के लिए कई बड़े-बड़े छात्र आंदोलन की अगुवाई की जिसकी वजह से राजस्थान विश्वविद्यालय और इनसे जुड़ी सभी सरकारी कॉलेज के छात्र छात्रों में राठौड़ काफी लोकप्रिय छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे राठौड़ के बारे में कहा जाता था कि जो भी मुद्दे छात्र हितों को लेकर उठाते थे उनके प्रभाव और उनकी लोकप्रियता की वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनकी बात को मानना ही पड़ता था, ऐसा कभी नहीं हुआ जब राठौड़ ने कोई मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन से की हो और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उस मांग को नहीं माना हो, छात्र राजनीति में ही राठौड़ अपनी दबंग छवि के रूप में जाने जाते थे और वह छवि सक्रिय राजनीति में आने के बाद अब तक कायम है, राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और एलएलबी और डी एल एल की डिग्री भी हासिल की, राठौड़ की युवाओं में और छात्रों में गजब की लोकप्रियता देखकर और उनकी दबंग छवि से प्रभावित होकर जनता दल ने उन्हें 1980 में चुरू जिले की विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा लेकिन राठौड़ अपना पहला चुनाव नहीं जीत पाए थे।

पार्टी से कभी भी नहीं की गद्दारी हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहे राठौड़

जिस दिन से राजेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा में शामिल हुए, उस दिन से ही राठौड़ पूरी तरह से भाजपा के प्रति समर्पित रहे, हालांकि इस दौरान भाजपा ने भी उन्हें खूब मान सम्मान दिया और अच्छे पदों पर बिठाया भी लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब पार्टी के बड़े नेताओं की आपस की लड़ाई में राठौड़ को बेवजह बीच में घसीटा गया। जिसकी वजह से उन्हें भी जहर का घूंट पीना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के प्रयासों में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और तन-मन-धन से पार्टी की सेवा करते रहे। विपक्षी दलों के नेताओं की बयान-बाजी को उन्हीं के अंदाज में राठौड़ ने पलट कर जवाब भी दिया, चाहे पार्टी के संगठन से जुड़ा मामला हो या फिर अपनी पार्टी की सरकार से जुड़ा कोई मामला हो, जब भी पार्टी को राठौड़ की जरूरत महसूस हुई राठौड़ दौड़कर आए और पार्टी ने जो भी उन्हें जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को निभाया विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव हर चुनाव में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, अब तक उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। हमेशा पार्टी के स्टार प्रचारक रहे और स्टार प्रचारक के दौरान भी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने में दिन-रात एक कर दिए। इसीलिए राजेंद्र राठौड़ को काफी भाग-दौड़ और मेहनत करने वाला नेता माना जाता है। राठौड़ ने कभी भी पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर काम नहीं किया, हमेशा पार्टी के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही राजनीति की। पिछले लोकसभा चुनाव में राठौड़ को टिकट मिलने की चर्चा थी, राठौड़ ने भी कह दिया था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे, हालांकि से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया था लेकिन पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी राठौड़ ने किसी भी तरह की कोई नाराजगी प्रकट नहीं की और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की उम्मीदवारों को जीतने के लिए दिन-रात मेहनत की। यही वजह है कि राठौड़ को निष्ठावान पार्टी का नेता माना जाता है।

अपनी पार्टी की सरकार में हर मुख्यमंत्री का दिल से दिया साथ

राजेंद्र सिंह राठौड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब-जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तब राजेंद्र राठौड़ ने हर मुख्यमंत्री का दिल से पूरा सपोर्ट किया, भैरव सिंह शेखावत सरकार में भी एक बार निर्दलीय विधायकों का समर्थन दिलवाने में राजेंद्र राठौड़ का बहुत बड़ा हाथ रहा था। इसी तरह से वसुंधरा राजे पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी तो वसुंधरा राजे के दोनों शासनकाल में राजेंद्र राठौड़ कैबिनेट मंत्री बने लेकिन सरकार से जुड़े हर विषयों को लेकर वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ से चर्चा करके ही कोई निर्णय लेती थी। राजस्थान विधानसभा में अपनी सरकार का बचाव करने के लिए राजेंद्र राठौड़ काफी दौड़ धूप और मेहनत किया करते थे। राजस्थान विधानसभा में सरकार को नीचा नहीं देखना पड़े इसके लिए अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श करके उन्हें आवश्यक सलाह देते रहते थे, उनके मन में यह भाव कभी भी नहीं आया कि मुझे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। वह हमेशा समर्पित भाव से अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के समर्थन में ढाल बनकर खड़े नजर आए और वर्तमान में भी प्रदेश की भजनलाल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हर तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं, हालांकि अभी राठौड़ विधायक नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार से जुड़े लोगों के साथ जरूरी विषय पर बातचीत करते रहते हैं और अपनी सलाह और राय भी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भी राजेंद्र राठौड़ के बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

राठौड़ को विरासत में नहीं मिली राजनीति, पिता उत्तमसिंह राठौड़ थे आरएसएस अधिकारी

आज राजेंद्र सिंह राठौड़ की गिनती भाजपा के टॉप नेताओं में होती है, राठौड़ ने सिर्फ अपने बूते पर कठिन संघर्ष और बुलंद हौसलों से राजस्थान की राजनीति में जो नाम कमाया है और भाजपा में खुद को साबित किया है वह अपने आप में बेमिसाल है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को विरासत में राजनीति नहीं मिली थी और शुरू के दो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही उनकी जगह अगर और कोई राजनेता होता और शुरू के दो चुनाव हार जाता तो फिर शायद वह तीसरा चुनाव नहीं लड़ता लेकिन राठौड़ ने तीसरा चुनाव भी लड़ा और फिर चुनाव जीते और फिर लगातार सात बार चुनाव जीते इस दौरान झूठे मुकदमों में जेल में भी गए लेकिन टूटे नहीं अपने हौसलों को बुलंद रखा और सच्चाई पर चलते रहे। समय निकालकर राठौड़ वकालत भी करते हैं हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजय मिलने के बाद राठौड़ के पास इस समय पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि या तो राठौड़ को आने वाले दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक नियुक्ति मिल सकती है या फिर भाजपा की केंद्रीय की नई टीम में उन्हें बड़ी भूमिका में रखा जा सकता है।

मंत्री रहने के दौरान भी बड़े विभागों का कुशलता से किया संचालन, खुद को श्रेष्ठ मंत्री के रूप में साबित किया

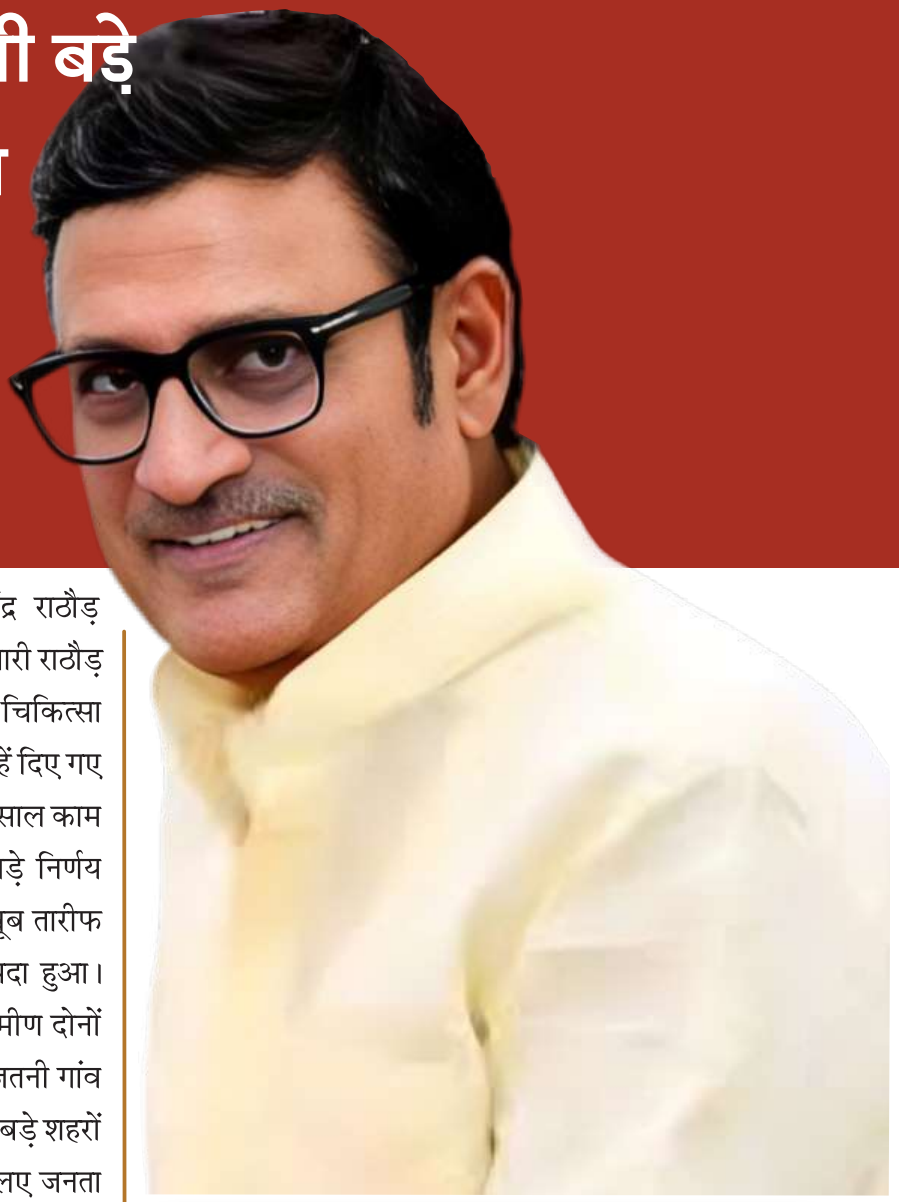

वसुंधरा राजे के दोनों शासनकाल में राजेंद्र राठौड़ कैबिनेट मंत्री रहे और कई बड़े-बड़े विभागों की जिम्मेवारी राठौड़ को दी गई। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, चिकित्सा विभाग और संसदीय कार्य मंत्री जैसे कई बड़े विभाग उन्हें दिए गए और इन सभी विभागों में उन्होंने बहुत शानदार और बेमिसाल काम करके दिखाया। कई बड़ी योजनाएं और कई बड़े-बड़े निर्णय लिए, जिनकी वजह से विभागों के कामकाज की तो खूब तारीफ हुई। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को भी खूब फायदा हुआ। राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी उन्हें बखूबी से थी, जितनी गांव की समस्याओं के बारे में वे जानकारी रखते हैं उतनी ही बड़े शहरों की समस्याओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए जनता से जुड़े विषयों के बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। इसी वजह से राजस्थान विधानसभा के अंदर उनके जो भाषण हुआ करते थे, वह काफी दमदार और तथ्यात्मक हुआ करते थे, जिन्हें हर कोई सुनना पसंद करता था। इसी वजह से राठौड़ जब राजस्थान विधानसभा में किसी भी विषय पर अपना भाषण देते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य चुपचाप उनकी बातों को सुना करते थे क्योंकि वे जो भी बात बोलते थे पूरी तैयारी के साथ रात भर स्टडी करके आते थे और फिर धारा प्रवाह हर विषय पर बारीकी से जानकारी दिया करते थे। जिसकी वजह से उनकी बातों को हमेशा विधानसभा सचिवालय और सरकार दोनों काफी गंभीरता से लेती थी।

प्रखर राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी नेता के रूप में खुद को साबित किया है जवाहरसिंह बेडम ने

मेवात क्षेत्र में तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने का लिया है संकल्प, ब्रज क्षेत्र को आबाद और खुशहाल करने की कोशिश, सनातन धर्म की रक्षा और गोवंश की सुरक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर, किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ गुर्जर आंदोलन में निभाई अग्रिम भूमिका

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी का जन्म राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और हिंदुत्व की विचारधारा के ठोस आधार पर ही हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी नेताओं की लंबी लिस्ट है, जो बिना किसी डर और संकोच के डंके की चोट पर सार्वजनिक सभाओं में सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, गोवंश की रक्षा और राष्ट्रवाद की बात को प्रमुखता से देश वासियों के समक्ष रखते रहे हैं। उन्हीं नेताओं में से एक शख्स ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली ब्रजभूमि से जन्मे और ब्रजभूमि की मिट्टी में खेलकूद कर बड़े हुए, अच्छी हाई प्रोफाइल पढ़ाई की और आज राजस्थान भाजपा के प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में खुद को साबित करके दिखाया है। जी, हां यहां बात हो रही है जवाहरसिंह बेडम, जो वर्तमान में प्रदेश की भजनलाल सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और प्रदेश के डीग जिले के तहत नगर विधानसभा सीट से वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए, बेडम का बातचीत करने का अंदाजा बिल्कुल निराला है। हर सवाल का हाजिर जवाब उनके पास होता है और हर सवाल का बहुत ही गंभीरता से तथ्यात्मक तरीके से जवाब देते हैं, हर मुद्दे पर और हर विषय पर उनकी अच्छी पकड़ होती है और अपने व्यवहार से और अपने बोलचाल की स्टाइल से विरोधी लोगों को भी अपने सामने सर झुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बेडम ने गुर्जर आंदोलन में किरोड़ीसिंह बैंसला के साथ गुर्जर समाज के हितों की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और अब भी गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के सर्वांगीण विकास और भाईचारे का माहौल बनाए रखने में गृहराज्य मंत्री के रूप में शानदार भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। बेडम ने गृहराज्य मंत्री के रूप में अपने विभाग में कई नवाचार और नए प्रयोग भी किए हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली और कार्यशैली में अच्छा बदलाव देखने को मिला है। इसी वजह से प्रदेश की भजनलाल सरकार में इनकी श्रेष्ठ मंत्री के रूप में गिनती होती है।

सपना होगा साकार

RISING RAJASTHAN

पुलिस रिकॉर्ड में उर्दू और फारसी के शब्दों के प्रयोग पर जवाहरसिंह ने लगाई पाबंदी

गृह राज्य मंत्री के रूप में जवाहर सिंह ने पुलिस रिकॉर्ड में उर्दू और फारसी के शब्दों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर एक नए नवाचार किया। पुलिस विभाग के किसी भी दफ्तर में कागजी प्रक्रिया में फारसी और दो शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पहले पुलिस विभाग के छोटे-बड़े सभी दफ्तर और पुलिस स्टेशन में अक्सर कागजी कार्रवाई में उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। इस बात को गृहमंत्री के रूप में जवाहरसिंह ने काफी गंभीरता से लिया और एक नया फरमान जारी करके उन्होंने फारसी-उर्दू के शब्दों को पूरी तरह से पुलिस विभाग के कार्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जवाहरसिंह का कहना है कि प्रदेश के पुलिस स्टेशन और पुलिस के अन्य दफ्तरों में फारसी और उर्दू शब्दों का कागजी कार्रवाई में जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुगल काल से ही नियमित रूप से होता आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस महकमे भी इन शब्दों का कार्य-प्रक्रिया में खूब इस्तेमाल होता था। पुलिस स्टेशन में भी कार्य-प्रक्रिया में उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। जिस पर जवाहरसिंह का कहना है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू और फारसी के शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए जिन शब्दों का लोग अर्थ ही नहीं समझे उनका इस्तेमाल करना कहां तक उचित है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया गया है और अब चाहे पुलिस स्टेशन हो और पुलिस विभाग का चाहे कोई-सा भी दफ्तर हो, वहां पर उर्दू और फारसी के शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता पूरा काम हिंदी में होता है ताकि लोग अच्छी तरह से भाषा को समझ सके और पुलिस की कार्रवाई को समझ सके।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वाजिद अली को हराया था कांटे की टक्कर में

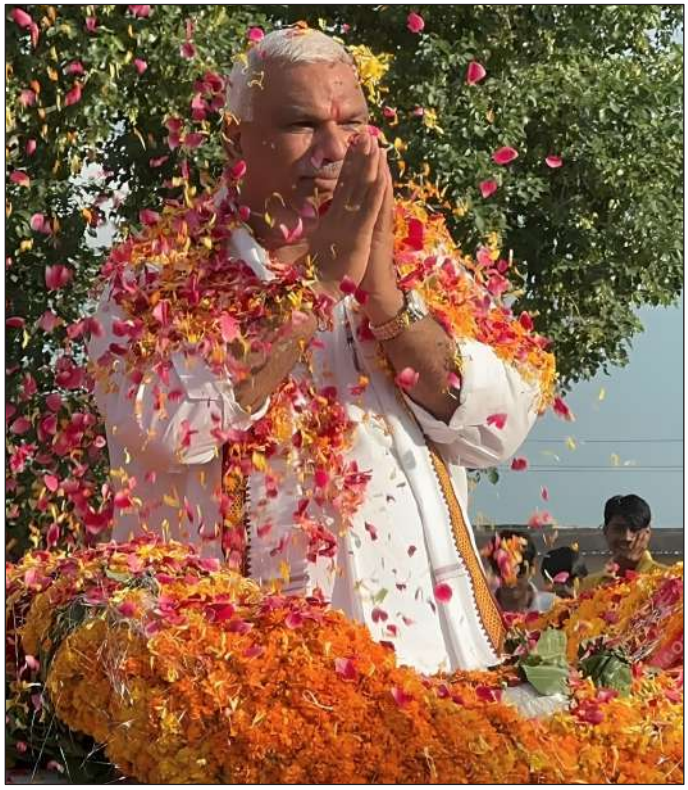

पिछले विधानसभा चुनाव में जवाहरसिंह बेडम ने कांग्रेस प्रत्याशी वाजिद अली को करीब 1600 वोटो के अंतर से हराया था, इस सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद भी जवाहरसिंह ने मौजुदा विधायक वाजिद अली को हराया, जो यह दिखाता है कि चुनाव से पहले ही जवाहर सिंह ने अपनी कार्यशैली अपने व्यवहार और अपने इरादों से क्षेत्र के लोगों में कितनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जवाहर सिंह को वोट किया, जिसकी वजह से उनकी जीत के रास्ते और आसान हुए, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कामा विधानसभा सीट से जवाहर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। वर्ष 2023 के चुनाव में उन्हें नगर सीट से भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की, जिस सीट पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या ज्यादा हो और उस सीट पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में जवाहर सिंह का जितना कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। यह अपने-आप में यह एक बड़ी राजनीतिक जीत थी, इसका कारण यही रहा कि जवाहर सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पारस्परिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की बजाय स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से उनकी जीत के रास्ते आसान हुए और हर जाति और बिरादरी के लोगों का उन्हें समर्थन में आये।

पूरे ब्रज क्षेत्र की खुशहाली और तरक्की के लिए पूरी तरह से समर्पित दिख रहे हैं जवाहर सिंह

पिछले एक दशक से ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग क्षेत्र के लोगों की ओर से लगातार की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठन ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग नियमित रूप से कर रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार के समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग को सही बताया लेकिन उन्होंने ब्रज विकास बोर्ड का गठन नहीं किया। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग जोर-जोर से उठ रही है, इसके लिए जवाहर सिंह बेडम ने खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग की है। हालांकि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बजट में ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट मंजूर किया है और क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद भी है कि इस बार प्रदेश सरकार ब्रज विकास बोर्ड का गठन कर ही देगी और वर्षों से चली आ रही उनकी मांग इस बार जरूर पूरी होगी क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और ब्रज क्षेत्र से उनका जमीनी जुड़ा रहा है। इधर गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह खुद ब्रज क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने जिस तरह से पत्र लिखा है, तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही क्षेत्र के लोगों की यह मांग पूरी हो जाएगी और जब ब्रज विकास बोर्ड का गठन होगा तो यह भी निश्चित है कि ब्रज क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और तेजी से होगा और ब्रज क्षेत्र के तहत आने वाले सभी गांव और इलाके तरक्की की और तेजी से आगे बढ़ेंगे, हालांकि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं के लिए अलग से बजट जारी किया है, जिसके फलस्वरूप ब्रज क्षेत्र में कई नए प्रोजेक्ट और कई नई योजनाएं संचालित की जा रही है लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अलग से ब्रज विकास बोर्ड के गठन से विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। इसलिए जवाहरसिंह बेडम मजबूती के साथ अपनी ही पार्टी की सरकार के समक्ष समय-समय पर ब्रज विकास बोर्ड के गठन की मांग रखते रहे हैं और इसके लिए वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलकर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं से अवगत करवा चुके हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा उनके पत्र पर गंभीरता से विचार करके बहुत जल्दी ही ब्रज विकास बोर्ड का गठन भी कर देंगे।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने कई बार कहा है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र नगर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास और तरक्की के रोडमैप के आधार पर काम कर रहे हैं, जिसमें हर गांव को आदर्श और विकसित गांव बनाने का उनका सपना है और इसी परिपेक्ष में गांव का मास्टर प्लान के आधार पर गांव का विकास किया जा रहा है। गांव में सभी तरह की आधारभूत सुविधा हो और गांव से शहरों की ओर लोगों का पलायन कम हो इसके लिए भी उनकी यही कोशिश रहती है कि गांव के लोगों को गांव में ही अगर अच्छा रोजगार मिल जाए तो फिर वह शहर की ओर भागेगा ही नहीं इसलिए बेडम एक तरफ जहां प्रत्येक गांव को विकसित और आदर्श गांव बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्रज क्षेत्र में कई तरह की विकास योजनाओं और प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिशों में भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 2 साल में ब्रज क्षेत्र में कई तरह के नए विकास कार्य संचालित हुए हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है इसलिए लोगों को यह उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा और जवाहरसिंह इन दोनों हस्तियों के होते हुए इस बार ब्रज क्षेत्र तरक्की के नए अध्याय के पन्ने जरूर लिखेगा।

पूरे मेवात क्षेत्र में तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं जवाहर सिंह

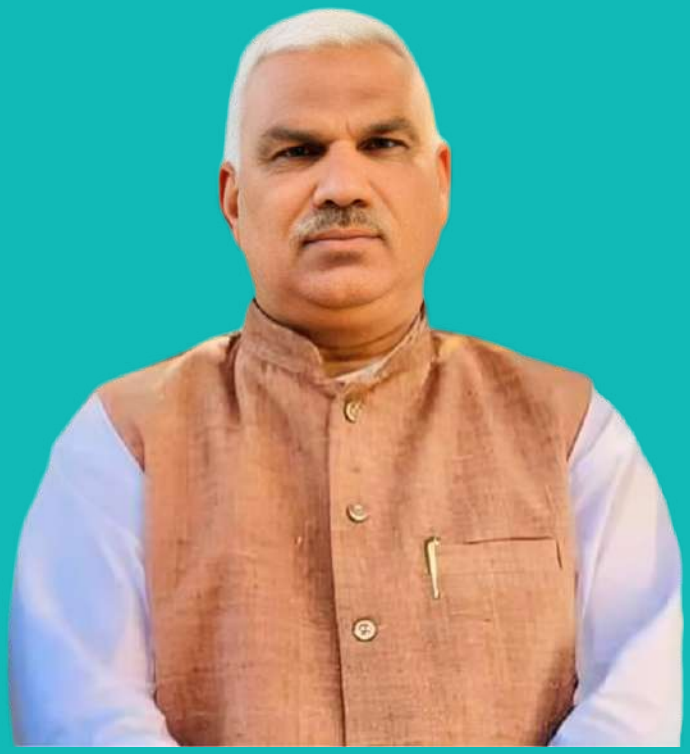

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया, जिसके कारण कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इसलिए गृहराज्य मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति को जड़ से खत्म किया जाए। अब लोगों को यह समझने में भी आने लगा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। जवाहरसिंह का कहना है कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से ही मेवात क्षेत्र में अपराध जगत से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हुए और अपराधों को लेकर मेवात क्षेत्र हमेशा राजस्थान में सुर्खियों में रहा। इसलिए मेवात क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान की जीत पर ताली बजाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना जरूरी है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के गुण गाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति हो, अगर वह भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलता है और भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और नगर विधानसभा क्षेत्र और आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्र में अपराध जगत से जुड़े लोगों की कार्यशैली और गतिविधियों पर पुलिस की निगाह है, पिछले दो साल में पूरे मेवात क्षेत्र में अपराध की गतिविधियों में तेजी से गिरावट आई है। साइबर क्राइम के मामलें काफी कम हुए हैं और कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति पर भी तेजी से अंकुश लग रहा है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी अब यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती है। इसलिए पिछले 2 साल में जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ही पूरे मेवात क्षेत्र में एक अलग-सा अच्छा और स्वस्थ माहौल देखने को मिल रहा है।

खुद को एक अच्छे गृह राज्य मंत्री के रूप में किया है साबित

इसमें कोई संदेह नहीं पिछले 2 साल में जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है, तब से प्रदेश में अपराधों में तेजी से कमी आई है। अन्यथा पिछले गहलोत सरकार के समय अपराध के मामलों में राजस्थान की छवि भारत में काफी धूमिल हुई थी। राजधानी जयपुर अब पूरे देश में सुरक्षित शहरों में दूसरे स्थान पर आ गया है। एक समय ऐसा था जब जयपुर में अपराध के मामले में बड़े महानगरों की तरह पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। लेकिन अब जयपुर देश का सबसे सुरक्षित दूसरे नंबर का सिटी बन गया है, जो यह दिखाता है कि राजस्थान पुलिस के कार्यशैली और उसके व्यवहार में क्रांतिकारी बदलाव आया है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को दिया जा सकता है, जानकार लोगों का कहना है कि जवाहर सिंह गृहमंत्री के रूप में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से जानते हैं, वह यह भी जानते हैं कि गृह राज्य मंत्री का चार्ज हाथ में लेने के बाद से ही जवाहर सिंह नियमित रूप से पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करके उनसे अपराधों को लेकर सलाह मशविरा करते रहते हैं और पुलिस विभाग की कार्यशैली और व्यवहार के बारे में फीडबैक लेते रहते हैं। अपनी ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश भी देते रहते हैं, इसके अलावा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बातचीत करके उनसे यह सलाह भी लेते रहते हैं कि पुलिस महकमे में और क्या-क्या नए प्रयोग किए जाएं? जिसकी वजह से पब्लिक में पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत हो और अपराध जगत से जुड़े लोगों में पुलिस को लेकर डर पैदा हो, जवाहर सिंह ज्यादा से ज्यादा नए प्रयोग और नवाचार करने में भी विश्वास करते हैं क्योंकि जवाहर सिंह एक अच्छे वकील भी हैं और वे यह भी जानते हैं कि सिर्फ ताकत के आधार पर आज के युग में अपराध की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा सकते। क्योंकि वर्तमान में साइबर अपराध देश और दुनिया की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसलिए जवाहर सिंह जानते हैं कि पुलिस अब परंपरागत तरीके से आगे अपना काम नहीं कर पाएगी, इसके लिए पुलिस को वर्तमान हालातों के मध्यनजर खुद को अपराधियों से निपटने के लिए हर तरह से सक्षम बनाना होगा। इसलिए पुलिस विभाग की जब भी कोई कार्यशाला या संगोष्ठी होती है, जवाहर सिंह अनुभवी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से पुलिस में किए जाने वाले नवाचारों के बारे में पूछते हैं और उनसे राय लेते हैं और जवाहर सिंह की हमेशा यही कोशिश रहती है कि नए-नए नवाचार और नए-नए प्रयोगों के माध्यम से पुलिस को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाए ताकि चतुर से चतुर अपराधी को भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके।

जवाहर सिंह नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस के बड़े अधिकारियों से तो मीटिंग करते ही हैं, इसके अलावा जिला स्तर पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों से भी बैठक आयोजित करके उनसे उनके काम के बारे में फीडबैक लेते रहते हैं। इसके कारण पुलिस अधिकारियों पर भी एक तरीके से राजनीतिक और सरकार का प्रेशर बना रहता है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही गृह विभाग था। जिसकी वजह से उनके पास काम का बहुत ज्यादा बोझ रहता था और पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी कोई ज्यादा मीटिंग नहीं होती थी, इसलिए पुलिस विभाग की कार्यशैली और फीडबैक उनके पास में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता था। इस तरह की शिकायत राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के विधायक किया करते थे और विपक्ष के विधायकों की यह मांग रहती थी कि अपराधों को देखते हुए एक अलग नेता को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जाए ताकि गृह डिपार्टमेंट का ठीक तरह से संचालन हो सके लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल तक गृह विभाग अपने पास ही रखा। उसी का नतीजा रहा कि प्रदेश में अपराध की गतिविधियां तेज गति से बड़ी और अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाया लेकिन वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर सिंह को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी और अब तक जवाहर सिंह ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उसी का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले दो सालों में हत्या, डकैती, लूट, चोरी अपहरण जैसी घटनाओं में तेजी से कमी आई है, अंतर राज्य बदमाशों की गैंग पर भी अंकुश लगा है, संगठित अपराध गिरोह पर भी अंकुश लगा है। इन सबको देखकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो विश्वास करके जिम्मेवारी जवाहर सिंह को सौंप थी उस विश्वास पर वह खरे उतर रहे हैं।

किरोड़ी बैसला के साथ गुर्जर आंदोलन में निभा चुके हैं अग्रणी भूमिका

जवाहर सिंह बेडम, गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और पूर्व में गुर्जर आंदोलन के दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुर्जर समाज के हितों की रक्षा और गुर्जरों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। इसीलिए प्रदेश के गुर्जर समाज में जवाहर सिंह का नाम काफी सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है। जवाहर सिंह जितने गंभीर नजर आते हैं, उतने ही काफी तेज-तर्रार नेता के रूप में भी माने जाते हैं, डर और खौफ उनके चेहरे पर कभी भी नजर नहीं आता। गुर्जर आंदोलन के दौरान उन्होंने कई-कई दिनों तक कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए किरोड़ी सिंह बैंसला भी जवाहर सिंह की काफी इज्जत किया करते थे। आज भी गुर्जर समाज के तमाम बड़े नेता इनका काफी सम्मान करते हैं, चाहे मानसिंह गुर्जर हो, महेंद्र खंडेला हो सभी नेता इनको काफी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी में मौजूद गुर्जर समाज के नेता भी जवाहर सिंह का काफी सम्मान करते हैं। क्योंकि इनका व्यक्तित्व इन्हें सबसे अलग बनाता है और इनका बातचीत का तरीका सबसे अलग और सबसे जुदा है। अपने विरोधी को कड़ी से कड़ी बात भी मीठे शब्दों में कहकर उसे अपने सामने सर झुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनकी यही खासियत उन्हें एक श्रेष्ठ राजनेता के रूप में साबित करती है। कुछ महीने पहले जब प्रदेश में गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आया था और विजय बैंसला ने जब गुर्जर समाज की महापंचायत में सरकार से समझौता होने की बात कही थी, इसके तुरंत बाद विजय बैसला से नाराज होकर गुर्जर समाज के सैकड़ो लोगों ने पैसेंजर ट्रेन को रोककर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। उस समय जवाहर सिंह ने रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी से फोन पर बातचीत की और फोन पर ही उन्होंने आंदोलनकारी को गंभीरता से समझाया, जिस पर आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए थे, जो यह दिखाता है कि जवाहर सिंह का गुर्जर समाज में इतना प्रभाव और वर्चस्व है। गुर्जर समाज के युवा उन्हें कितना चाहते हैं, अन्यथा जब रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के सैकड़ो युवा बैठे हुए थे तब ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन अब लंबा चलेगा। लेकिन जवाहर सिंह का व्यक्तित्व और उनकी बात करने का तरीका ही था, उसकी वजह से उग्र आंदोलनकारी ने रेलवे ट्रैक को छोड़ दिया।

विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले की जांच प्रक्रियाओं पर भी नजर रखते हैं जवाहर सिंह

पिछली गहलोत सरकार के समय करीब दो दर्जन सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले उजागर हुए थे और इन मामलों की जांच तत्कालीन गहलोत सरकार के समय ठीक तरह से शुरू नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। क्योंकि भजनलाल जानते थे कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की विदाई में इन पेपर लीक मामलों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए प्रदेश के युवाओं का भरोसा हासिल करने के लिए इन सब पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए पुलिस की एक अलग से टीम का गठन किया। इसके बाद विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पुलिस की जांच की प्रक्रिया तेजी से संपादित हो रही है, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और अब भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। चाहे बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला हो या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला या फिर वनरक्षक भर्ती परीक्षा का मामला सभी मामलों की जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, यहां तक की राजस्थान लोकसभा के पूर्व मेंबर तक की गिरफ्तारी हुई। इन सभी पेपर लीक के मामलों की जांच प्रक्रिया पर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। पुलिस को किसी के भी दबाव में नहीं आने की बात कही गई है। जवाहर सिंह नियमित रूप से इन सभी परीक्षाओं के बारे में पारदर्शक तरीके से जांच के लिए प्रेरित करते रहते हैं और चाहे कोई कितना ही बड़ा राजनेता हो या फिर चाहे को कितना ही प्रभाव वाला व्यक्ति हो, अगर उसकी पेपर लीक में भूमिका नजर आती है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए भी भजनलाल सरकार ने पूरी तरह से पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने पेपर लीक के मामलों की जांच के संबंध में कई बार पत्रकारों से कहा है कि पहले भी कई मगरमच्छों को पकड़ा जा चुका है और जो मगरमच्छ पकड़े जाने हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। किसी भी बड़े मगरमच्छ को छोड़ेंगे नहीं चाहे कोई भी हो।

प्रमुख राष्ट्रवाद, सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुत्व की विचारधारा से दिल से जुड़े हैं जवाहरसिंह

गुर्जर समाज में जवाहर सिंह पहले ऐसे दबंग और ऊर्जावान नेता माने जाते हैं, जो खुलकर सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ-साथ हिंदुत्व की बात भी डंके की चोट से कहते हैं। हालांकि जवाहर सिंह किसी भी दूसरे धर्म पर हमला बोलने में विश्वास नहीं करते लेकिन उनका यह कहना है कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति को सिर्फ भारत की भाषा बोलनी चाहिए और भारत माता के प्रति समर्पित होना चाहिए और अगर कोई भारत माता के प्रति समर्पित नहीं रहता है तो फिर उसे भारत में रहने का कोई हक भी नहीं है, जवाहर सिंह सनातन धर्म की रक्षा और उनके प्रचार-प्रचार में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, उनका मानना है कि आदिकाल से हिंदुस्तान में सनातन धर्म का ही कालखंड हुआ करता था और सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं। इसलिए सनातन धर्म के प्रति जवाहर सिंह की जबरदस्त आस्था है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार हैं। गोवंश की रक्षा के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। गोवध और गो तस्करी के मामलों को लेकर उन्होंने कई कड़े कदम उठाए हैं और कड़े कानून बनवाए हैं। पहले मेवात क्षेत्र में गो तस्करी और गो हत्या के मामले खूब हुआ करते थे, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार के गठन के बाद से इन मामलों में तेजी से कमी आई है, इसकी वजह यही है कि जवाहर सिंह इस तरह के मामलों को लेकर काफी सख्त हैं और पुलिस को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए काफी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं।

अमित शाह और भजनलाल के सपने को साकार कर रहे गौतम कुमार

> "सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल राजस्थान, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति के गठन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी"

जयपुर। सहकारिता क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, यह इसी से साबित हो जाता है कि उन्होंने खुद अपनी सरकार में वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इसकी जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह को दी, मोदी और अमित शाह दोनों सहकारिता के महत्व को बारीकी से समझते हैं, दोनों ही जानते हैं कि अगर भारत सहकारिता के क्षेत्र में मजबूत होगा तो कई तरह की समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिलेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रत्येक व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी क्रम में प्रदेश की भजनलाल सरकार भी केंद्र सरकार के निर्देशन में सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से काम करती हुई दिख रही है, जैसा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मानते हैं कि सहकारिता में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है, पिछले 20 माह में भी भजनलाल सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में कई बड़े फैसले और निर्णय लिए। जिसकी वजह से प्रदेश के कृषि, दुग्ध, लघु एवं कुटीर उद्योग, रियल एस्टेट, रोजगार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण इत्यादि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का गठन करके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस कार्य में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार की कार्य शैली और उनके नवाचारों की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है क्योंकि पिछले 1 साल में ही प्रदेश में लक्ष्य से ज्यादा नई सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है, बड़ी संख्या में गोदाम का निर्माण हुआ है तथा कृषि और पशुपालन व्यवसाय में भी सहकारिता के क्षेत्र में लिए गए निर्णय से अच्छे बदलाव देखने को मिले हैं। जिसकी वजह से प्रदेश के किसान और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है तो दूसरी ओर प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से सहकार उत्पाद की वजह से महिलाओं की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हुई है अकेले सहकार क्षेत्र में किए गए नवाचारों का फायदा अन्य क्षेत्रों को भी मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को तो मजबूती मिल ही रही है, इसके अलावा जो लोग सहकारिता से जुड़ रहे हैं, उनके परिवारों में भी खुशियां छाई हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार की मेहनत, उनकी कार्यशैली और उनके नवाचारों से सहकारिता के क्षेत्र में काफी कुछ नयापन और पारदर्शिता की झलक देखने को मिली है, जिसकी वजह से प्रदेश के लोग सहकारिता से लगातार जुड़ रहे हैं। खासतौर से किसान और पशु-पालक सहकारिता के आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

भजनलाल की आकांक्षाओं पर खरे उतरे गौतम कुमार

केंद्रीय स्तर पर सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में सहकारिता विभाग को ऐसे शख्स के हाथों में देना चाहते थे, जो इस महत्वपूर्ण विभाग में क्रांतिकारी और चमत्कारिक बदलाव ला सके। क्योंकि भजनलाल शर्मा यह जानते थे कि अगर सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में ठीक तरह से काम नहीं हुआ तो फिर अमित शाह से फटकार भी मिल सकती है। इसलिए उन्हें गौतम कुमार की योग्यता और उनके अनुभव पर पहले से पूरा भरोसा था, क्योंकि भजनलाल शर्मा प्रदेश भाजपा के कई सालों तक प्रदेश महामंत्री रहे और करीब 20 साल तक प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान गौतम कुमार से उनकी मुलाकात बहुत पहले से ही थी क्योंकि गौतम कुमार चित्तौड़गढ़ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्ष 2013 में बड़ी सादड़ी से विधायक भी रह चुके थे। इसलिए भजनलाल शर्मा यह भी जानते थे कि गौतम कुमार अच्छे पढ़े लिखे हैं, साफ-सुथरी छवि के हैं काफी मेहनती भी हैं और ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं तथा सहकारिता के क्षेत्र को ठीक तरह से समझते भी हैं। इसलिए उन्होंने काफी सोच-विचार करके ही सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी गौतम कुमार को दी, उनका यह निर्णय अब सच भी साबित हो रहा है क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की सक्रियता और भूमिका पूरे देश में अग्रणी है। चाहे नई सहकारी समिति के गठन का मामला हो या फिर किसानों को खाद, बिजली, दवाई इत्यादि सहकारी समितियां के माध्यम से वितरण करने की बात हो या फिर किसानों को सहकारी समितियां के माध्यम से ऋण देने की बात हो या फिर सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन देने की बात हो या फिर प्रदेश में सहकार रोजगार मिले या फिर सहकार उत्पादन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात हो या फिर पशुपालकों को सहकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण देने की बात हो। ऐसे अनेक उदाहरण है जिनकी वजह से सहकारिता के क्षेत्र में अमित शाह भी राजस्थान के प्रदर्शन को लेकर काफी खुश और प्रभावित है। इसलिए यह तो कहना ही पड़ेगा कि गौतम कुमार ने अपने अच्छे कार्यों की वजह से कहीं ना कहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों का दिल जीत लिया है।

सहकारी समितियां के संचालक मंडल से संवाद करने के लिए बड़ा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं गौतम कुमार

प्रदेश में करीब 41000 सहकारी समितियां हैं और 4000 इंपैक्ट्स हैं। पिछले 1 साल में करीब हजार नई सहकारी समितियां का गठन किया गया है और 5400 सहकारी समितियां को कंप्यूटराइज्ड भी किया गया है लेकिन पिछले कई सालों से ही सहकारिता विभाग में कई तरह की कमियां, अनियमिताएं, भ्रष्टाचार, लापरवाही, समय पर चुनाव नहीं होना, सहकारी समितियां की ऑडिट समय पर नहीं होना इत्यादि कई विषयों को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विरोधी दल के सदस्य समय-समय पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन विधायकों का सवाल खड़े करना गलत भी नहीं है, यह कटु सत्य है कि राजस्थान में सबसे पहले चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की दोनों ही दलों की सरकार सहकारिता विभाग को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आई और ना ही अब से पहले कोई सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग की दिशा और दुर्दशा को सुधारने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाया, जिसका नतीजा यह रहा कि सहकारिता विभाग अपनी कार्यशैली, कमियों और भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना रहा, लेकिन यह भी कहना पड़ेगा की पिछले 20 महीने सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण रहे, सहकारिता को जन आंदोलन बनाने में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं, वह अप्रत्याशित हैं। पिछले 20 महीना में सहकारिता विभाग में जो नए प्रयोग किए गए, नए फैसले लिए गए और विभागीय स्तर पर गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और कमियों को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, वह काफी सराहनीय है। उसी का परिणाम है कि प्रदेश में सहकारिता से हर कोई जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहा है। यह अब राजस्थान में एक बड़ा जन-आंदोलन बन चुका है, जिसमें हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार की शिकायत आम बन गई थी, इसलिए भले ही राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी रहा हो लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का इस विभाग के प्रति भरोसा कमजोर हो रहा था। इस बात को सहकारिता मंत्री गौतम कुमार अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस विभाग के कार्यशैली को पारदर्शक बनाने के लिए अब तक अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब को-ऑपरेटिव कोड लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और लाल फीता शाही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि गौतम कुमार अब तक प्रत्येक जिले में जाकर ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियां के संचालक मंडल के साथ बैठक करके तमाम तरह के हालातो की जानकारी लेंगे, सहकारी समितियां की वस्तु स्थिति का आकलन करेंगे, जो गड़बड़ियां और लापरवाही सामने आएगी, उन्हें दूर करने का हाथों-हाथ प्रयास करेंगे, यह पहली बार होगा जब कोई सहकारिता मंत्री सहकारी समितियां के द्वार तक खुद जाएगा।

प्रदेश में हर एक ग्राम पंचायत समिति के गठन का संकल्प

प्रदेश में भजनलाल सरकार हर व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ना चाहती है, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। पहले यह संकल्प लिया गया था कि आगामी 2 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति के गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सहकारिता मंत्री गौतम कुमार की कोशिश यही है कि 2 साल नहीं बल्कि आगामी 1 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति के गठन का काम पूरा कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने विभागीय स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया हुआ है और पंचायत स्तर पर सहकारी समिति के गठन के काम पर खुद नजर रख रहे हैं। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने यह भी कहा है कि सिर्फ सहकारी समिति का गठन करने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि प्रत्येक सहकारी समिति को पांच एक्टिविटी से जुड़ना ही होगा यानी सरकारी समिति का गठन सिर्फ सरकार से योजनाओं का फायदा उठाने के लिए ही नहीं बल्कि जमीन पर सरकारी समिति को काम करके दिखाना होगा। अब से पहले ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी समितियां बनी हुई है, उनमें कई तरह की कमियां और भ्रष्टाचार की शिकायतें बड़े पैमाने पर कई सालों से मीडिया की सुर्खियों में बनी रही है, चाहे किसानों को खाद, बीज, दवाइयां वितरण करने का मामला हो या फिर लोन वितरण करने का मामला हो हर जगह कई तरह की शिकायतें मिलना आम हो गई थी, इसलिए इस बार प्रदेश की भजनलाल सरकार सहकारी समितियां के गठन की प्रक्रिया से लेकर सहकारी समितियां की कार्यशैली, उनकी जिम्मेदारी और उनके दायित्व को लेकर भी काफी गंभीर है। इसके अलावा सहकारी समितियां के ऑडिट प्रक्रिया को लेकर भी सरकार काफी सख्त है। हालांकि सहकारी समितियां में कंप्यूटराइज्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन अभी सभी सहकारी समितियां में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को लागू करना संभव नहीं है फिर भी सहकारी समितियां को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियां को कंप्यूटराइज्ड करने के कार्य पर भी भजनलाल सरकार काफी गंभीर दिख रही है लेकिन इतना जरूर है। अब से पहले जिस तरह से कई तरह की शिकायतें और कमियां सहकारी समितियां के संदर्भ में मिला करती थी उन पर भजनलाल सरकार का कठोर नियंत्रण है और इस काम में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार पूरी ईमानदारी से कम कर रहे हैं।

रियल स्टेट के कारोबार से जुड़ी सहकारी समितियां को लेकर गौतम कुमार है काफी गंभीर

प्रदेश में रियल स्टेट कारोबार से भी सहकारिता का जुड़ाव है लेकिन यह भी सत्य है कि प्रदेश भर में रियल स्टेट के कारोबार से जुड़ी कई समितियां ऐसी हैं, जो नियम और कानून के खिलाफ काम कर रही हैं और अवैध कालोनियां विकसित करने में इनका बड़ा योगदान है। कई समितियां ऐसी भी हैं, जो फर्जी पट्टे काटने के काम में व्यस्त हैं। इस तरह की कई सहकारी समितियां को ब्लैकलिस्टेड भी किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद भी यह सहकारी समितियां सक्रिय हैं। उपभोक्ताओं को इन सहकारी समितियां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती, इसलिए भोले-भाले लोग इन सहकारी समितियां के जंजाल में फंसकर लाखों रुपए गवा देते हैं क्योंकि इस तरह की सहकारी समितियां फर्जी लेटर पैड और कागज के आधार पर लोगों को भूखंडों के फर्जी पट्टे जारी कर देती हैं। इस तरह के मामले राजधानी जयपुर में ही कई थानों में कई सालों से पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द बने हुए हैं। इस तरह के मामले जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, आए दिन इस तरह के मामले पुलिस में दर्ज होते रहते हैं। इसलिए

नियम और कानून के खिलाफ काम करने वाली सहकारी समितियां को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार काफी सख्त हैं, पदभार ग्रहण करने के दौरान भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान गौतम कुमार ने कहा था कि अपने विभाग में सुनिश्चिता से काम हो और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर अच्छे माहौल में कार्य हो। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को साफ निर्देशित किया है, विभाग में चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी और कर्मचारी क्यों ना हो अगर वह गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक रियल स्टेट कारोबार में सहकारी समितियां की ओर से फर्जीवाड़ा करने की बात है, इस विषय को लेकर भी गौतम कुमार काफी सख्त हैं।

सरकारी बैंकों की ज्यादा से ज्यादा नई शाखा खोलने और कृषि के अलावा अन्य कामों के लिए भी ऋण देने को लेकर गंभीर है भजनलाल सरकार

प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार का मानना है कि प्रदेश में सहकारी बैंकों की नई शाखा ज्यादा से ज्यादा खुले ताकि जरूरतमंद लोगों को लोन लेने में सुविधा रहे। इसके अलावा गौतम कुमार यह भी चाहते हैं कि सहकारी बैंक सिर्फ किसानों तक ही सीमित ना रहे बल्कि अन्य क्षेत्र में नया काम शुरू करने वाले लोगों को भी सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की जाए तो सहकारिता के आंदोलन को और गति मिलेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा सहकारिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रदेश की भजनलाल सरकार की कोशिश भी यही है कि राष्ट्रीय सहकारी बैंकों की नई शाखाएं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा स्थापित हो ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण हासिल करने में अच्छी सुविधा मिल सके। इसके अलावा प्राथमिक सहकारी बैंक, जो घाटे की वजह से गुमनामी की गलियों में खो गए हैं, उन बैंकों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भी भजनलाल सरकार प्रयासरत है। इसके लिए घाटे में चल रहे इन बैंकों की रिकवरी के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। करीब ढाई सौ करोड रुपए की इन बैंकों की रिकवरी कर ली गई है। कुल मिलाकर सहकारी बैंकों की कार्यशैली को मजबूत करने, सहकारी बैंक में व्याप्त कमियां, लापरवाही और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी प्रदेश की भजनलाल सरकार काफी गंभीर है और ठोस प्रयत्नों के माध्यम से सहकारी का क्षेत्र से जुड़े, सभी बैंकों की व्यवस्थाओं को नया लुक और मजबूती देने का प्रयास कर रही है।

प्रदेश में करीब एक करोड़ 20 लाख लोग जुड़े हैं सहकारी समितियां से

प्रदेश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग सहकारी समितियां से जुड़े हुए हैं और लगातार इन समितियां से लोगों के जुड़ने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह समितियां प्रदेश में कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इसलिए प्रदेश की भजनलाल सरकार सहकारिता उपयोगिता को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए सहकारिता मजबूत होगी तो जो क्षेत्र सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उनमें भी मजबूती आएगी। जिसकी वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और जो लोग सीधे सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उनके परिवारों में भी खुशियां आएगी, इसलिए केंद्र कि मोदी सरकार भी सहकारिता से आमजन को जोड़ने के प्रयास में मजबूती से काम कर रही है और इसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी प्रेषित कर रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार भी इसी कोशिश में जुटी हुई है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सहकारिता से जुड़े, जिससे राजस्थान के विकसित राज्य बनने का संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।

भाजपा के समर्पित और कर्मठ नेताओं में गौतम कुमार की होती है गिनती, पूर्व में 2013 में भी रह चुके हैं विधायक

वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव में गौतम कुमार चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इससे पहले वर्ष 2013 की विधानसभा चुनाव में भी बड़ी सादड़ी से भाजपा की टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इससे पहले चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर भी गौतम कुमार ने शानदार काम करके दिखाया था और पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए इन्होंने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। गौतम, भाजपा के समर्पित और कर्मठ नेता माने जाते हैं, इनकी अच्छा व्यक्तित्व ही इनकी पहचान है। इनका बेहद सरल, सौम्य व्यवहार रहता है, ईमानदार छवि के राजनेता होने के साथ-साथ हर काम को गंभीरता से लेने का इनका अपना अलग स्टाइल है। जिसके आधार पर अब तक प्रदेश भाजपा ने भी इन्हें जिस-जिस काम की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेवारी को बखूबी से निभाया और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें सहकारिता विभाग की जो जिम्मेदारी दी है, उसको भी अब तक बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है।

सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गोदाम के निर्माण को लेकर भी गंभीर हैं गौतम कुमार

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गोदाम निर्माण के कार्य को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि एफसीआई, एनसीसीएफ इत्यादि किराए पर गोदाम लेने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गोदाम का निर्माण करके आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ जा सकता है। गौतम कुमार का कहना है कि सहकारिता अब कृषि, पशुपालन और रियल एस्टेट कारोबार से ही जुड़ा नहीं रह गया है बल्कि इसका जुड़ाव कई क्षेत्रों से है और लगातार नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता की भागीदारी बढ़ रही है यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दोनों सहकारिता के क्षेत्र को जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं। सहकारिता के इस व्यापक स्वरूप की वजह से प्रदेश के किसानो, पशुपालकों को भी काफी फायदा हो रहा है। सहकार उत्पाद से जुड़ी लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, महिलाएं आत्मविश्वासी बनी है और आत्मनिर्भर होने लगी हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछले 20 महीने राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी रहे। यही वजह है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से काफी प्रभावित है।

चुनाव के दौरान ही अमित शाह ने कर ली थी 'हीरे' की परख

इन्दिरा गॉधी के लिए दिए गये बयानों से मशहूर हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के कार्यो से जयपुर और दिल्ली दोनों खुश, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग के नए कलेवर से कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों को मिल रही है राहत

जयपुर। गृहमंत्री अमित शाह को राजनीतिक गलियों में यूं ही लोग भाजपा का चाणक्य नहीं कहते, शाह जितने चतुर हैं उतने ही सामने वाले का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि यह शख्स राजनीति के लायक है या नहीं इसीलिए भाजपा में उनकी ओर से लिया गया, प्रत्येक निर्णय पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से हिंदुस्तान में लोकप्रियता की बुलंदियों को छू रही है और दुनिया की नंबर वन राजनीतिक पार्टी बन गई है, शाह वर्ष 2014 से ही भाजपा के नंबर वन कुशल रणनीतिकार बने हुए हैं और उन्होंने अब तक पूरे देश में पार्टी में छुपी हुई, कई नौजवान प्रतिभाओं को छांटकर उन्हें अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया और वे नेता आज अपने कार्यों से खुद की योग्यता तो साबित कर ही रहे हैं और भाजपा की लोकप्रियता को भी चार चांद लगा रहे हैं, उन नेताओं में एक नाम अविनाश गहलोत का भी है जो वर्तमान में भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन गहलोत की राजनीतिक कुशलता और योग्यता को अमित शाह ने वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही पहचान लिया था। जब उन्होंने गहलोत के प्रचार की चुनावी सभा में उपस्थित लोगों से यह कह दिया था कि आप गहलोत को जिता दो बाकी का काम मैं देख लूंगा, यानी चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने यह मन में ठान ली थी कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो गहलोत को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे ही, बाद में यह बात सच भी साबित हुई प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। अविनाश गहलोत चुनाव जीते तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब पाली जिले में खासतौर से जैतारण के लोगों में यही चर्चा है कि अमित शाह को लोग यूं ही चाणक्य नहीं कहते, उनमें इंसान की परख करने का अनोखा गुण है, जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी भी शाह को अपना दाहिना हाथ मानते हैं, अविनाश गहलोत यह तो जानते थे कि पीएम नरेंद्र मोदी और शाह के फैसले और निर्णय हमेशा चौंकाने वाले होते हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को बढ़िया अवसर जरूर देते हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरी बार के विधायक चुने जाने के बाद ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का तोहफा मिल जाएगा लेकिन गहलोत मंत्री पद को तोहफा नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं, जो विश्वास पार्टी हाई कमान में उन पर किया। उस विश्वास को बरकरार रखने में वे अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे, गहलोत के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पिछले करीब 2 साल में जो काम हुए हैं और जो निर्णय इस विभाग की ओर से लिए गए हैं, उनसे प्रदेश के कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के परिवारों में खुशियां छा गई है। कमजोर परिवारों को हर तरह से संबल मिला है। इस विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर किए जा रहे कार्यों से विभाग की कार्य प्रणाली और कार्यशैली में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जिसमें भ्रष्टाचार की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गहलोत के कार्यों से खुश हैं तो दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेता भी इस नौजवान मंत्री के कामों और उनके नवाचारों से काफी प्रभावित है।

पांच बार के विधायक और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल को हराना आसान नहीं था

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में अविनाश गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र गोयल को 13995 वोटो के अंतर से हराया था। सुरेंद्र गोयल 5 बार के विधायक थे और वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते थे लेकिन वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की और फिर 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जैतारण से टिकट भी दिया लेकिन अविनाश गहलोत से चुनाव हार गए, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि सुरेंद्र गोयल को हराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि गोयल का जैतारण ही नहीं बल्कि पूरे पाली जिले में बहुत अच्छा राजनीतिक प्रभाव था और अगर कोई व्यक्ति पांच बार विधायक रह जाता है तो उसके पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी भी नहीं रहती, लेकिन वे पिछले चुनाव में अविनाश गहलोत को नहीं हरा सके, जबकि गहलोत को टिकट देने से नाराज भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने एक संत को चुनाव मैदान में उतार भी दिया था। इसके बावजूद भी गहलोत ने अपने अच्छे व्यवहार, कार्य शैली और पब्लिक से जुड़ाव के आधार पर चुनाव जीता। गहलोत के चुनाव जीतने का एक कारण यह भी था कि वर्ष 2018 में जैतारण से पहली बार विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने हमेशा अपने घर के दरवाजे सभी जाति और बिरादरी के लोगों के लिए खुले रखे और आधी रात को भी कोई पीड़ित उनके पास किसी भी तरह की मदद के लिए आ जाता था, तो उसे पूरा मान-सम्मान के साथ अपने घर में बिठाते और बहुत ही सम्मान के साथ उसकी शिकायत को सुनते और उसका निवारण भी करवाते, जबकि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मजबूती के साथ राजस्थान विधानसभा में आवाज उठाई और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और सरकार को कहीं ना कहीं उनके मांग को मनाना ही पड़ता था, जिसके कारण उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य भी करवाए। इसलिए क्षेत्र के लोगों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी और अपने व्यवहार से हर जाति और बिरादरी के लोगों को दिल से जोड़ रखा था, इसका उन्हें चुनाव में फायदा मिला, दोबारा से जैतारण से विधायक चुने गए।

बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी और राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बताकर अविनाश गहलोत देश भर में हुए चर्चित

अविनाश गहलोत की गिनती भाजपा के प्रखर वक्ता के रूप में होती है, इन्होंने अपने बयानों से कई बार राजस्थान की राजनीति में बवंडर भी मचाया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इनके बयानों से राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन भी किये। गहलोत के बयान राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई दिनों तक सुर्खियों में रहे, गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में एक बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी बता दिया था। इसके बाद कई दिनों तक राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, इस बयान से उन्हें देशभर में गहलोत को पहचान मिली। इसी तरह से गहलोत ने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाने की बात पर बिना नाम लिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दे दी थी तो दूसरी तरफ बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी। इस बयान को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और विधायकों ने गहलोत के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, धरने प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किये लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मौका मिलता है। गहलोत कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर टीका-टिप्पणी करके माहौल को काफी गर्म कर देते हैं और राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं, उनके इन बयानों से भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ हुई है और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की निगाहें भी हमेशा गहलोत पर टिकी रहती है।

गहलोत के आचार-विचार और जीवन चरित्र में संघ का प्रभाव

अविनाश गहलोत छात्र जीवन से ही राष्ट्र प्रेम, जन सेवा की भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं, छात्र जीवन से ही संघ की शाखों में अपनी उपस्थिति दिखाने लगे थे। जिसकी वजह से इनके जीवन चरित्र और आचार-विचार में संघ का प्रभाव साफ दिखता है, हमेशा से राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए आ रहे हैं। अनुशासित जीवन शैली है और बिना किसी डर के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपने विचार खुलकर रखते हैं और मौका मिलते ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर व्यंग्य बाण के माध्यम से जुबानी हमले भी बोलते हैं जो कई बार बड़ा विवाद के कारण बन जाते हैं, जिस पर कई बार हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अविनाश गहलोत के मिजाज कभी नहीं बदला, हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर टीका-टिप्पणी करते नजर आए, लेकिन हर जाति और बिरादरी के लोगों के कल्याण और विकास के कार्य में कभी-भी भेदभाव नहीं करते सबको समान दृष्टि से देखते हैं। खासतौर से कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से मंत्री नहीं बनने से पहले भी काम करते थे और अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी कमजोर वर्गों के परिवार वालों के लिए संबल बने हुए हैं।

एक नहीं प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय में की छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में भी निभाई भूमिका

अविनाश गहलोत छात्र जीवन से ही काफी प्रखर और स्पष्ट वादी व्यक्ति रहे हैं, बिना डर और संकोच के स्पष्ट बात छात्र जीवन से ही कहते रहे हैं और प्रदेश के तीन बड़े विश्वविद्यालय में इन्होंने दमदार तरीके से छात्र राजनीति की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में भी अच्छी भूमिका निभाई। प्रदेश के राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में भी काम करते रहे, वकालत की पढ़ाई भी की, बिजनेस भी किया और राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दिखाते रहे, कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में गहलोत की सक्रियता और लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई से जुड़े नेता इन्हें छात्र जीवन से ही पहचानने लगे थे। पाली और आसपास के जिलों में गहलोत छात्र जीवन से ही अपनी अच्छी पहचान बना चुके थे। जिसकी वजह से नगर पालिका चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट भी दिया गया लेकिन चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद भी गहलोत ने जैतारण और आसपास के इलाके के लोगों से मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रखा और हर जाति और बिरादरी के लोगों के सुख-दुख में अपनी उपस्थित दिखाते रहे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इन्हें जैतारण भाजपा युवा मोर्चा के संगठन में अच्छे पदों पर नियुक्ति दी। जैतारण में युवा मोर्चा संगठन में गहलोत ने श्रेष्ठ काम करके दिखाया। इसके बाद नमो ऐप का इन्हें संयोजक भी बनाया गया और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिस भी पद पर जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेवारी को उन्होंने शानदार तरीके से निभाया जिसकी वजह से भाजपा के जयपुर मुख्यालय में बैठे बड़े नेताओं के दिलों में गहलोत ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। उसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल का टिकट काटकर भाजपा के रणनीतिकारों ने गहलोत को उम्मीदवार बनाया और गहलोत ने चुनाव में जीत भी दर्ज की। बाद में 2023 के चुनाव में भी सुरेंद्र गोयल जैसे बड़े नेता को हराया। इस तरह से गहलोत का भारतीय जनता पार्टी में अब तक का बहुत ही शानदार और सफल कार्यकाल रहा है और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने अब तक अच्छा काम करके दिखाया है।

सक्रिय मंत्री के रूप में माने जाते हैं अविनाश गहलोत

प्रदेश की भजनलाल सरकार में अविनाश गहलोत काफी युवा मंत्री है और माली समाज से ताल्लुक रखते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काफी सोच समझ कर ही गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी है। वर्तमान परिपेक्ष में यह मंत्रालय अपने आप में एक बड़ी चुनौती का मंत्रालय माना जा सकता है, क्योंकि इस मंत्रालय का सीधा जुड़ाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी इत्यादि से है, यह भी जग जाहिर है कि आजकल एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। इस मामले में डॉ. किरोड़ी मीणा जैसे नेता समाज के निशाने पर आ चुके हैं, इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि कठिन और विपरीत परिस्थितियों में गहलोत को इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मिली। जब गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी, तब किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि गहलोत इतनी गंभीरता और कुशलता से इस विभाग का संचालन कर पाएंगे, क्योंकि गहलोत युवा है और अनुभव के आधार पर कई लोगों का कहना था कि शायद ही गहलोत इस विभाग को ठीक तरह से संभाल पाए लेकिन यह भी सत्य है कि गहलोत ने हाई प्रोफाइल स्टडी की है प्रदेश के तीन प्रमुख विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, वकालत के पेशे से भी जुड़े हैं और युवा अवस्था में ही सफल व्यापारी भी बने हैं। इसलिए भले ही गहलोत की उम्र कम हो लेकिन अनुभव, नवीन प्रयोग और नवाचारों को लागू करने में इन्होंने बड़े-बड़े सीनियर नेताओं के अनुभवों को भी अब पीछे छोड़ दिया है और जिस गंभीरता के साथ और जिस समर्पित भाव के साथ इन्होंने मंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण विभाग का अब तक संचालन किया है, वह अद्वितीय और ऐतिहासिक माना जा सकता है क्योंकि विभाग में भ्रष्टाचार जैसी एक भी मामूली शिकायत अब तक नहीं मिली है। विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम किया जा रहा है। नियमित रूप से विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हैं और विभाग की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं का नियमित रूप से फीडबैक लेते रहते हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश भी देते रहते हैं, मंत्री बनने के बाद विभाग में सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल सेवा आरंभ की गई, जिसमें विभाग की ओर से संचालित की जा रही सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी है जो कोई भी देख सकता है और इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत अपना आवेदन इत्यादि विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस विभाग की सभी कागजी प्रक्रिया ऑनलाइन है इसलिए ना तो कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश बची है और ना ही लेट लतीफ जैसी कोई शिकायत किसी काम को लेकर यहां पैदा हो सकती है क्योंकि विभाग का यह पोर्टल सब कुछ बयां कर देता है।

विभाग की जिम्मेवारी पाकर खुद को काफी भाग्यशाली मानते हैं अविनाश गहलोत

अविनाश गहलोत बचपन से और छात्र जीवन से ही जितने मुखर और प्रखर बोलने में है उतना ही इनका दिल अंदर से कोमल है, वैसे मारवाड़ी अंचल के लोग कोमल हृदय वाले भी होते हैं। अविनाश गहलोत के बारे में भी कहा जाता है कि वह किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को देखकर काफी भावुक हो जाते हैं और उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करके ही सांस लेते हैं, गहलोत के ऐसे मिजाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शायद पहले से ही वाकिफ थे इसीलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके हाथ में दी। इस विभाग की जिम्मेवारी को हाथ में लेकर गहलोत भी खुद को खुशनसीब मानते हैं और यह समझते हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ा नेक काम करने का तोहफा उन्हें दिया है, क्योंकि यह विभाग कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए काम कर रहा है। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जैसे क्षेत्र में तो सुधार करना है ही इसके अलावा बाल कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवापेंशन और सामाजिक कल्याण विभाग और अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश भर में संचालित किया जा रहे हॉस्टल इत्यादि कार्य सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करने का एक बहुत बढ़िया मौका गहलोत समझ रहे हैं इसीलिए विभाग के कामकाज को लेकर गहलोत पहले दिन से ही पूरी तरह से सक्रिय हैं और विभाग की हर योजना का हर जरूरतमंद व्यक्ति फायदा उठाएं इसके लिए उन्होंने विभाग की कार्यशैली और कागजी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया हुआ है ताकि विभाग के कामकाज को लेकर कोई उंगली ना उठा सके। कमजोर तबके के लोग और वंचित वर्ग के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसके लिए प्रदेश-भर में विभाग की ओर से नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाता है। समय-समय पर विशेष कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यहां तक की विभाग की ओर से घर जाकर जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उस जरूरतमंद व्यक्ति से कागजी करवाई जाती है ताकि वह योजना का फायदा उठाने से वंचित न रह जाए, इन सभी विषय पर गहलोत पूरा फोकस रखते हैं क्योंकि इस तरह का बड़ा नेक काम करने का उन्हें पता नहीं फिर मौका मिले या नहीं, इसलिए उन्होंने पिछले 2 साल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में कई बड़े नए प्रयोग किये, कई क्रांतिकारी बदलाव किये और नियमित रूप से जिला स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते रहते हैं और हकीकत का पता लगाने के लिए मौके पर जाकर लोगों से पूछताछ करते हैं, चाहे बाल सुधार हाउस हो या फिर हॉस्टल हो। प्रदेश भर में भ्रमण करके मौके पर जाकर हालातो का जायजा भी लेते हैं और अधिकारियों बराबर निर्देशित करते रहते हैं, इसीलिए गहलोत भजनलाल सरकार के काफी सक्रिय मंत्री माने जाते हैं।

गहलोत को विरासत में नहीं मिली राजनीति

अविनाश गहलोत को विरासत में राजनीति नहीं मिली है बल्कि आज उन्होंने अपनी खुद की मेहनत, अपने व्यवहार और अपने कार्य से जनता से मिले स्नेह की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से जुड़े नेताओं और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं के दिलों में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, नगर-निकाय का पहला चुनाव हारने के बाद भी गहलोत ने हौसला बनाए रखा और अपने पब्लिक टच को रोजाना मजबूत करते रहे जिसके कारण क्षेत्र में लोकप्रिय होते गए और अपने राजनीतिक करियर को तेजी से आगे बढ़ाते रहे। आज गहलोत की आयु भले ही कम है लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, ऐसा मुकाम बहुत कम लोग हासिल करते हैं। बड़ी बात यह है कि मंत्री बनने से पहले जो मिजाज और जो व्यवहार गहलोत का हुआ करता था, वही मिजाज और वही व्यवहार उनका अब भी है। उनके घर के दरवाजे पहले भी हमेशा हर जाति, बिरादरी के लोगों के लिए खुले रहते थे और आज भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी आवास के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आज भले ही मंत्री होने की वजह से जयपुर में रहना, उनकी मजबूरी बन गया हो लेकिन नियमित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं और लोगों से पहले की तरह मिलते-जुलते रहते हैं। क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए अपना खुद का निजी स्टाफ अपने निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त किया हुआ है जो गहलोत की अनुपस्थिति में खुद ऑफिस में रहकर लोगों की शिकायत को सुनते हैं और शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। गहलोत अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय-समय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं और जयपुर में भी अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की तकलीफों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। भाजपा के स्थानीय संगठन को भी गति देने में अविनाश गहलोत शुरू से ही अग्रणी भूमिका में नजर आए, जिसकी वजह से क्षेत्र के छोटे-बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उनकी अच्छी छवि है और एक समर्पित और कर्मठ भाजपा नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए संघ के बड़े नेताओं का भी इन पर हमेशा आशीर्वाद रहा है और मंत्री बनने के बाद भी संघ की शाखाओं में जब भी मौका मिलता है, अब भी पहले की तरह संघ की जरूरी पोशाक पहनकर पहुंच जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अविनाश गहलोत ने आज जो कुछ मुकाम हासिल किया है, वह सिर्फ अपनी मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पित भाव से किया है। काम करने की वजह से और जन-सेवा के माध्यम से उन्होंने भाजपा में अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम नेता बना पाते हैं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलवर

पहला सुख निरोगी काया

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

कुष्ठ रोग मानव ज्ञात सबसे पुरानी बीमारी है। इस बीमारी के बारे में जानकारी और उल्लेख कई धर्म ग्रन्थों, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता जैसे औषधोपचार में मनुस्मृति के नियमों में और बाद के कानून कायदों में देखने को मिलता है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

कुष्ठ रोग धीरे-धीरे फैलने वाला बहुत कम संक्रामकता वाला कीटाणु जनित रोग है। यह रोग माइक्रोबेक्टीरियम लेप्रा नामक बेक्टीरिया द्वारा फैलता है। इस बेक्टीरिया को माईक्रोस्कोप यंत्र द्वारा आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है। यह बेक्टीरिया लाल रंग के दण्डाणु की तरह दिखाई देता है और टी.बी. के जीवाणु से मिलता जुलता है।

कुष्ठ रोग कैसे फेलता है?

पाये गये कुष्ठ रोगी जो कि संक्रामक अवस्था में पहुंच गये, वो रोगी जहां रहते है। वहां पर इन रोगियों के छिकने/खांसने /धुंकने से बैक्टीरिया के वातावरण में फैलने की आशंका रहती है, क्योकि इन संक्रामक रोगियों के नाक की श्लेष्मा में ये कीटाणु बहुतायत से पाये जाते है। कीटाणु नाक की झिल्ली या चमड़ी से निकलकर सांस द्वारा या फिर चमड़ी द्वारा दूसरे व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते है। आमतौर पर कुष्ठ रोगियों में से सिर्फ 15 से 20 रोगी ही संक्रामक होते है।

कुष्ठ रोग के प्रकार

कुष्ठ रोग दो प्रकार का होता है-

(1) संक्रामक- ऐसे व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनके शरीर में कीटाणु हवा द्वारा प्रविष्ट कर जाते है। संक्रामक रोगियों के नाक की श्लेष्मा में ये कीटाणु बहुतायत से पाये जाते है। इन रोगियों को मल्टी बैसिलरी MB भी कहते है।

(2) असंक्रामक- ऐसे व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उनके शरीर में कीटाणु पुरे शरीर में ना फैलकर केवल अंग विशेष में ही सीमित रहते है ऐसे रोगियों के नाक की श्लेष्मा में ये कीटाणु नहीं पाये जाते है। अत: इन असंक्रामक रोगियों को पोसी बैसिलरी PB कहते है।

कुष्ठ रोग के लक्षण

त्वचा पर आंशिक या पूर्ण सुन्नता वाले / संवेदनाहीन चकते / धब्बे त्वचा से हल्के या गहरे रंग के।
चकते की त्वचा उभरी हुई होना।
चेहरे की त्वचा चमकदार या तैलीय होना।
त्वचा पर गठाने होना।
कान की लोब मोटी/ गठाने होना।
भोंहे के बालों का झडना।
नाक की हड्डी का विकृत होना।
हाथ पैर की नसों का मोटा होना।
कोहनी / घुटना एवं टखने में दर्द झनझनाहट / दोनों होना।
छुने पर ठण्डे/गर्म का अहसास ना होना।
हथेली में सुन्नता होना व हाथों / पैरों में सुन्नता होना।
हाथों में जख्म / दर्द रहित घाव हथेली का जलना।
नर्व, त्वचा, आँख को प्रभावित करने वाला रोग है चकते युक्त।

राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त

जयपुर टाइम्स

(जयपुर एवं चूरू से एक साथ प्रकाशित)

जयपुर टाइम्स

भजनलाल सरकार में वीआईपी कल्चर का त्याग करने वाले पहले मंत्री "संजय शर्मा"

जयपुर टाइम्स

राजनीति में दादी से आगे निकली दिया कुमारी

दिया कुमारी ने अब तक तीन चुनाव लड़े और तीनों जीते

जयपुर टाइम्स

किसान और पशुपालकों में ओम पूनिया की लोकप्रियता चरम पर

सामाजिक सरोकारों के कामों में भी पूनिया की संत - महात्मा जैसी भूमिका

जयपुर डेयरी के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी लोकप्रिय है ओम पूनिया

जयपुर टाइम्स

पहले वाजपेई का अब नरेंद्र मोदी का दिल जीता "अश्विनी वैष्णव" ने

जयपुर टाइम्स

पिता के सपनों को साकार कर रहे झाबर सिंह खर्रा, शहरों को नया लुक देने के लिए कर रहे है कड़ी मेहनत

जयपुर टाइम्स

भजनलाल शर्मा ने रचा इतिहास, डेढ़ लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संग मनाया "रक्षाबंधन"

जयपुर टाइम्स समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ने के लिए क्लिक करें

www.jaipurtimes.org

https://www.youtube.com/@JaipurTimes

@JaipurTimes2

@jaipurtimes.news

जयपुर टाइम्स में संवाददाता बनने के लिए, विज्ञापन एवं समाचार प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें :-

Email- jaipurtimes2007@gmail.com (समाचारों के लिए)

Email- jaipurtimes.adv@gmail.com (विज्ञापनों के लिए)

मो. 7014217770

प्रधान कार्यालय- सी 588, 4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड़, रोड़ नं. 14, सीकर रोड़, जयपुर (राजस्थान)